



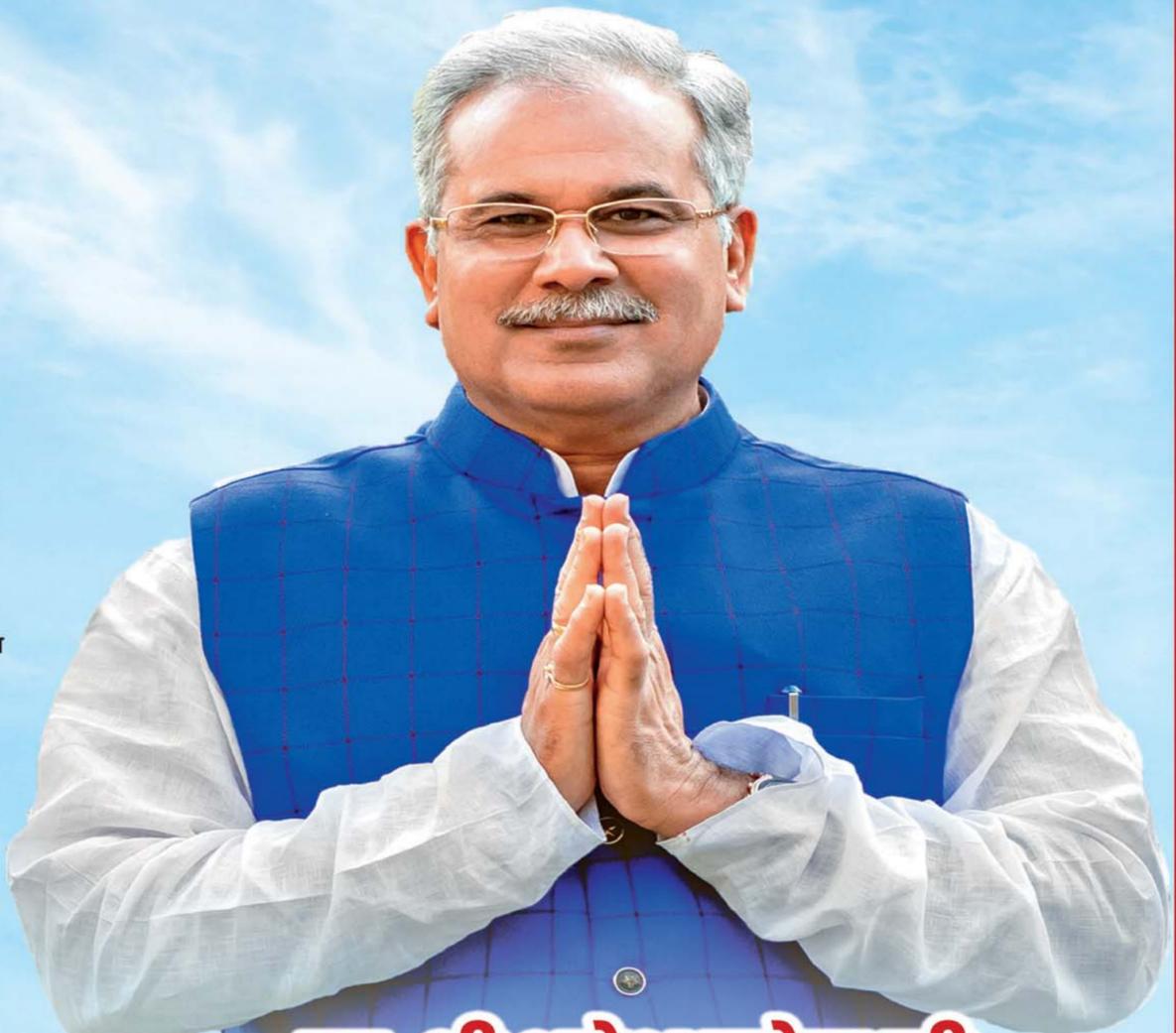
बीते 5 वर्षों का स्वर्णिम कार्यकाल, हर वर्ग हुआ खुशहाल राष्ट्रीय स्तर पर दिलाई छत्तीसगढ़ को नई पहचान

भूपेश भैया आप जियो हज़ारों साल

न्याय, सरोकार व इच्छाशक्ति से बना छत्तीसगढ़ मॉडल

भूपेश बघेल जी के द्वारा 5 साल में किए गए महत्वपूर्ण कार्य

- लगभग 18 लाख किसानों का 10000 करोड़ का कृषि ऋण माफ किया गया
- किसानों का लगभग 350 करोड़ सिंचाई कर माफ किया गया
- 2500 रुपए से अधिक कीमत पर प्रति क्विंटल धान खरीदने वाला पहला राज्य
- किसानों का धान प्रति एकड़ 20 क्विंटल खरीदा गया
- राम वन गमन पर्यटन परिपथ का विकास
- शहीद महेंद्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना
- राजीव गांधी किसान न्याय योजना
- गोधन न्याय योजना
- राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना
- 65 प्रकार की लघु वनोपज की समर्थन मूल्य में खरीदी
- मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना
- मुख्यमंत्री सुपोषण योजना
- डॉ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना
- छत्तीसगढ़ में 3 नए मेडिकल कालेज की स्थापना
- छत्तीसगढ़ के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाफ योजना के तहत लगभग 42 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को अभी तक लगभग 3500 करोड़ की छूट दी गई है
- मुख्यमंत्री मितान योजना, हरेली, तीजा, मां कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस, छठ पूजा की अवकाश
- मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना, पढ़ई तुहर दुआर योजना



मा. श्री भूपेश बघेल जी पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़



छत्तीसगढ़िया संस्कृति के ध्वज वाहक मान. भूपेश बघेल जी ला जन्मदिन के गाड़ा-गाड़ा बधाई



गिरीश देवांगन

पूर्व अध्यक्ष - छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम
(पूर्व कैबिनेट मंत्री दज्जि)
उपाध्यक्ष - प्रदेश कांग्रेस कमेटी

अभिषेक बोरकर

प्रदेश अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ असंगठित कामगार
एवं कर्मचारी कांग्रेस

अनुराग श्रीवास्तव

प्रदेश उपाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ असंगठित कामगार
एवं कर्मचारी कांग्रेस

सुशील सन्नी अग्रवाल

पूर्व अध्यक्ष - छत्तीसगढ़ भवन एवं
अन्य सन्निमाण कर्मकार कल्याण मंडल, BOCW
(पूर्व कैबिनेट मंत्री दज्जि)

प्रधानमंत्री आदर्श गांव पाकुरभाट में साढ़े 3 वर्ष से अधिक समय पहले स्वीकृत हुए कार्य आज तक अधूरे, जिम्मेदारों ने हड़प ली राशि

पायनियर संवाददाता < बालोद
www.dailypioneer.com

जिले में जिम्मेदारों ने प्रधानमंत्री आदर्श गांव में विकास कार्यों के लिए जारी किए गए राशि में भी बंदरबाट और भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और ये जिम्मेदार और कोई नहीं भाजपा पार्टी से ही तालुक रखने वाले जनप्रतिनिधि हैं। मामला जनपद पंचायत बालोद अंतर्गत ग्राम पंचायत जगतरा के आश्रित ग्राम पाकुरभाट का है। जिसे प्रधानमंत्री आदर्श गांव में शामिल है। 2019-20 में इस गांव को प्रधानमंत्री आदर्श गांव के लिए चयनित किया गया था। विभिन्न विकास कार्य इस गांव के लिए स्वीकृत हुए थे। जिसमें ड्राफ्टिंग घर से चंद्रिका घर तक 6 लाख लागत से सीसी रोड, वाई-14 में साढ़े 5 लाख लागत से नाली निर्माण, प्राथमिक शाला में डेढ़ लाख लागत से शौचालय व शौचालय निर्माण कार्य स्वीकृत किये गए थे। लेकिन कई कार्य अधूरे हैं। इतना ही नहीं पंचायत के द्वारा राशि भी निकाल ली गई है, और कार्य को पूर्ण ही नहीं



लाख से प्राथमिक शाला में अज्ञात निर्माण, वाई-12 में 6 लाख से सीसी रोड निर्माण, वाई-14 में 5 लाख से सीसी रोड निर्माण तथा प्राथमिक शाला में डेढ़ लाख की लागत से मूत्रालय व शौचालय निर्माण कार्य स्वीकृत किये गए थे। लेकिन कई कार्य अधूरे हैं। इतना ही नहीं पंचायत के द्वारा राशि भी निकाल ली गई है, और कार्य को पूर्ण ही नहीं

कराया गया है। आलम यह है कि 3 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कार्य अधूरे पड़े हैं। इतना ही नहीं 3 वर्ष में कार्य पूर्ण नहीं होने से ऑगनबाड़ी केंद्र जर्जर हो चुका है, यहाँ झड़ियां उग गई हैं।

3 साल में 6 से अधिक नोटिस सरपंच को हुआ जारी-जनपद पंचायत से मिली जानकारी अनुसार ग्राम

पाकुरभाट में ऑगनबाड़ी में अज्ञात एवं पथवे निर्माण, प्राथमिक शाला में अज्ञात, शौचालय एवं निर्माण कार्य अधूरे हैं। जनपद पंचायत ने ग्राम पंचायत जगतरा को उक्त तीनों निर्माण कार्य की कुल राशि साढ़े 10 लाख में आधी राशि मार्च 2021 में जारी कर दी थी। बावजूद 3 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं

किया जा सका है। जबकि इन 3 साल में सरपंच को कार्य पूर्ण करने 6 बार से अधिक नोटिस भी जारी की गई है, बावजूद नोटिस को सरपंच के द्वारा अनदेखा किया गया, और आज तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया। राशि प्राप्त कर कार्य ही नहीं पूर्ण किया गया। 3 साल में सरपंच के द्वारा नोटिस के जवाब में यथाशीघ्र कार्य को प्रारम्भ कर पूर्ण करने

का आश्वासन दिया जाता रहा है। लेकिन आज तक कार्य को पूर्ण नहीं किया गया। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री आदर्श गांव का सपना इस गांव के लिए महज सपना बन के रह गया है। जिम्मेदारों के द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श गांव के तहत जारी की गई राशि में बरती गई अनियमितता एवं बंदरबाट को लेकर अब जनपद पंचायत को

पंचायती राज अधिनियम धारा 92 के तहत वसूली की कार्यवाही की जानी चाहिए। दो नए गांव हुए चयनित-उल्लेखनीय हो कि जिले में 2019-20 में रुद, नवागांव, कोसा, पाडवारा, सुखरी, पाकुरभाट और रायपुर गांव प्रधानमंत्री आदर्श गांव के रूप में चयनित हुए थे। वही इस सत्र दो नए गांव तमोरा और पड़कीभाट प्रधानमंत्री आदर्श गांव के लिए चयनित किये गए हैं। जहाँ विभिन्न तरह के विकास कार्य किये जायेंगे। लेकिन इन नए दोनो गांवों के लिए शासन से राशि जारी नहीं किया गया है। जैसे ही फंड जारी होगा, यहाँ विकास के निर्माण कार्य किये जायेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री आदर्श गांव के नोडल आदिवासी विभाग है, यहाँ राशि आती है फिर उस राशि को एंजेंसी को दे दी जाती है। जिसके बाद पूर्ण कार्यों की पूर्णतः और उपयोगिता लेकर शासन को प्रेषित की जाती है। आदर्श ग्राम का सपना- 'आदर्श ग्राम' वह है जिसमें लोगों को विभिन्न बुनियादी

सेवाओं तक पहुँच प्राप्त हो ताकि समाज के सभी वर्गों की न्यूनतम जरूरतें पूरी हो सकें और असमानताएँ न्यूनतम हो सकें। इन गांवों में सभी बुनियादी ढाँचे होंगे और उनके निवासियों को ऐसी सभी बुनियादी सेवाओं तक पहुँच होगी, जो एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, जिससे ऐसा माहौल बनेगा जिसमें हर कोई अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने में सक्षम होगा। इसके लिए अनुसूचित जाति वर्ग के बहुलता वाले गांव का चयन प्राथमिकता से किया गया है, परंतु जो बुनियादी ढांचे इस गांव को मिलनी चाहिए, उससे यह गांव जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से कोसो दूर नजर आ रहा है।

अपूर्ण कार्यों का साढ़े 10 लाख एएस में 50 प्रतिशत राशि जारी किया गया था, सरपंच को 6 से अधिक बार नोटिस जारी की गई है, लेकिन अब तक कार्य अधूरे हैं, अब आगे कियमानुसर कार्यवाही की जाएगी। -पीताम्बर यादव, सीईओ, जनपद पंचायत, बालोद

उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने 6 स्थानों पर रोड, नाली, निर्माण के लगभग 35 लाख के नये कार्य करवाने भूमिपूजन किया

पायनियर संवाददाता < रायपुर
www.dailypioneer.com

रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने नगर निगम जोन 3 के तहत शंकरनगर वाई क्रमांक 30 के क्षेत्र में जनहित में जनसुविधा विस्तार हेतु अधोसंरचना मकद के अंतर्गत 35 लाख रूपी की स्वीकृत लागत से नवीन गुना वाली गली हनुमान मंदिर के सामने रोड निर्माण, सी टाईप से जनता टाईप मकान तक नाली निर्माण एवं कवर्ड करवाने कार्य, प्रिमिला राजपुत के निवास से सुदीप किराना तह नाली निर्माण, कवर्ड कार्य, सीसी रोड निर्माण, गोरखापारा में विजय सोनी के मकान से शर्मा के मकान तक नाली निर्माण कार्य, डॉ. आशा नेवले के मकान के पास से होते हुए प्रतीक लुनावत के मकान के सामने से होते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने तक सीसी रोड सड़क निर्माण कार्य एवं अशोक शर्मा के निवास के



सामने से बसंत साहू के निवास के सामने तक कांक्रीट सड़क निर्माण कार्य हेतु श्रीफल फोडकर एवं कुदाल चलाकर नये विकास कार्यों का भूमिपूजन नगर निगम जोन 3 के जोन अध्यक्ष डॉ. प्रमोद साहू, शंकरनगर वाई पार्चड सुमन राम प्रजापति, सामाजिक कार्यकर्ता सुनील परेतकर, जोन 3 जोन कमिश्नर जसदेव सिंह बाबरा सहित

रायपुर। भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के तहत कार्य करने वाले राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति और छत्तीसगढ़ स्टेट बैंकर्स समिति, रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संभावित लाभार्थियों के बीच जन-जागरूकता के लिए 23 अगस्त, 2024 को सुबह 11.00 बजे से आईटीआई-सड्डू, रायपुर में एक कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों के बीच योजना के लाभों और उपलब्ध होने वाले ऋण सुविधाओं के बारे में जागरूक करना है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र बैंकों के राज्य प्रमुख, ऋण प्रसंस्करण प्रकोष्ठों के एजीएम, विभिन्न जिलों के अग्रणी बैंक प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के निदेशक, आईटीआई माना, रायपुर, आईटीआई-सड्डू, रायपुर आजीविका महाविद्यालय, रायपुर, आरएसईटीआई, रायपुर, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, रायपुर के प्राचार्यों के साथ ही साथ पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी और योजना का बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु इस कार्यलय/ सेमिनार में शामिल होंगे।

रायपुर। भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के तहत कार्य करने वाले राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति और छत्तीसगढ़ स्टेट बैंकर्स समिति, रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संभावित लाभार्थियों के बीच जन-जागरूकता के लिए 23 अगस्त, 2024 को सुबह 11.00 बजे से आईटीआई-सड्डू, रायपुर में एक कार्यशाला/सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों के बीच योजना के लाभों और उपलब्ध होने वाले ऋण सुविधाओं के बारे में जागरूक करना है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र बैंकों के राज्य प्रमुख, ऋण प्रसंस्करण प्रकोष्ठों के एजीएम, विभिन्न जिलों के अग्रणी बैंक प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के निदेशक, आईटीआई माना, रायपुर, आईटीआई-सड्डू, रायपुर आजीविका महाविद्यालय, रायपुर, आरएसईटीआई, रायपुर, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, रायपुर के प्राचार्यों के साथ ही साथ पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी और योजना का बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षु इस कार्यलय/ सेमिनार में शामिल होंगे।

राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित तेलीबांधा तालाब मेरिन ड्राईव में किया गया जिसमें तथ्याकथित चमत्कारों के वैज्ञानिक प्रदर्शन, नागरिकों एवम विद्यार्थियों को अर्धविक्षास निर्मूलन से संबंधित किताबें, पंपलेट वितरित किए गए। अर्धविक्षास निर्मूलन समिति छत्तीसगढ़ विज्ञान सभा, तकशील, सहित सहयोगी संगठनों के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में डॉ. नरेन्द्र दाभोलकर को श्रद्धांजलि दी गई। आयोजन में अर्धविक्षास निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ. दिनेश मिश्र ने कहा देश में अर्धविक्षासों व सामाजिक कुरीतियों के कारण प्रतिवर्ष हजारों लोग प्रताड़ना के शिकार होते हैं। वर्तमान में वैज्ञानिक जागरूकता की



आवश्यकता है। जिसके लिए लगातार अभियान चलाए जाने की जरूरत है, जिससे लोगों के बसे अर्धविक्षास व सामाजिक कुरीतियां हटाई जा सकेंगीं। विज्ञान सभा के अध्यक्ष विश्वास मेथ्राम ने कार्यक्रम के आयोजन की जानकारी दी। तकशील परिषद के डॉ. आरके सुब्रह्मण्य ने काथित चमत्कारों के वैज्ञानिक प्रदर्शन किए था चमत्कारों की वैज्ञानिक सत्यता बताई गई। संजोव खुद शाह ने

वास्तुशास्त्र से जुड़े अर्धविक्षासों की जानकारी दी। अयोजन को अजू मेथ्राम, निसार अली ने भी संबोधित किया कार्यक्रम में आ. एम. ए. ए. अध्यक्ष डॉ. राकेश गुआ, उमाशंकर ओझा, अधीर, जयश्री भगवानानी, सहित अनेक नागरिक स्कूली छात्र उपस्थित थे कार्यक्रम में नागरिकों व छात्रों को अर्धविक्षास निर्मूलन संबोधित किताबें, पंपलेट वितरित किए गए आम लोगों की जिज्ञासा का समाधान किया गया।

धरसीवा विधायक अनुज शर्मा एवं आयुक्त अंबिनाश मिश्रा ने जोरा, कचना, आमासिवनी का निरीक्षण किया

पायनियर संवाददाता < रायपुर
www.dailypioneer.com

धरसीवा विधायक अनुज शर्मा एवं नगर पालिक निगम रायपुर के आयुक्त अंबिनाश मिश्रा ने पंडित मोतीलाल नेहरु वाई क्रमांक 8 के पार्चड गोपेश साहू, नगर निगम जोन 9 जोन कमिश्नर संतोष पाण्डेय, कार्यपालन अभियंता के.के. शर्मा सहित जोन के अन्य संबंधित अधिकारियों, गणमान्यजनों की उपस्थिति में जोन 9 के तहत आने वाले जोरा, कचना, आमासिवनी रहवासी क्षेत्र का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। धरसीवा विधायक अनुज शर्मा ने निगम आयुक्त अंबिनाश मिश्रा सहित अधिकारियों की उपस्थिति में किये गये निरीक्षण के दौरान जोन 9 के तहत जोरा क्षेत्र में जोरा स्कूल के सामने मैदान का समतलीकरण करवाने, स्कूल परिसर में जर्जर भवन को तोड़ने की कार्यवाही करने जोरा तालाब एवं पानी टंकी के समीप जनसुविधा हेतु बाजार विकसित करने का कार्य शीघ्र करवाने के निर्देश दिये। धरसीवा



विधायक ने निगम आयुक्त एवं वाई 8 के पार्चड सहित निरीक्षण के दौरान जोन 9 के तहत कचना क्षेत्र में खेल मैदान एवं मुक्तिधाम विकसित करने का कार्य शीघ्र करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने पुराना सामुदायिक भवन की व्यवहारिक आवश्यकता के अनुरूप सुधार मरम्मत का कार्य करवाने निर्देशित किया। कचना में नगर निगम जोन 9 के माध्यम से निर्माणधीन सामुदायिक भवन का कार्य तेज गति से करवाकर शीघ्र जनहित में जनसुविधा हेतु पूर्ण करवाने के निर्देश दिये गये। धरसीवा विधायक ने नगर निगम आयुक्त एवं वाई 8 के पार्चड सहित आमासिवनी क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान तालाब का सौंदर्यीकरण करवाने एवं बाजार विकसित करने के निर्देश दिये।

छ: सूत्रीय मांगों को लेकर नवयुवत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री अरूण साव को सौंपा ज्ञापन

पायनियर संवाददाता < कुम्हारी
www.dailypioneer.com

उपमुख्यमंत्री एमम विभागीय मंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, अरूण साव से नवयुवत अधिकारी/कर्मचारी कल्याण संघ छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा 6 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी निवास में भेंट किया गया, जिसमें कुम्हारी से हरिकिशन पावरिया महामंत्री दुर्गा संभागे ने बताया कि नगरीय निकायों के कर्मचारियों को प्रतिमाह के दिनांक 1 को वेतन भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से सुनिश्चित हो। नगरीय निकायों में अन्य विभाग की भाँति ओड्ड पेंशन योजना शीघ्र ही लागू किया जावे। नगरीय निकायों में मृतक कर्मचारी के परिवारों को शीघ्र ही संपाग स्तर पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया जावे। नगरीय निकायों में कर्मचारियों के पदोन्नति हेतु शीघ्र ही पद सृजन किया जावे। नगरीय निकायों में टेका पद्धति शीघ्र ही समाप्त किया जावे। नगरीय निकायों के कर्मचारियों को 6 वें व 7वें वेतनमान



की एरिसर्स की राशि भुगतान हेतु आदेश प्रसारित किया जावे आदि बातें रखी गईं। इस भेंट के क्रम में संच के प्रदेश अध्यक्ष राजेश सोनी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश तिवारी, पंकज मेथ्राम, प्रदेश सचिव ऋषभ ठाकुर, प्रदेश कोषाध्यक्ष संदीप चंद्राकर, प्रदेश उपाध्यक्ष माला प्रकोष्ठ शिल्प्य मेथ्राम, प्रदेश कोषाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ अनु सोनी, प्रदेश महामंत्री विकास सिंह ठाकुर, हरिकिशन पावरिया, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष मालिहोश शर्मा, प्रदेश प्रवक्ता ललित साहू, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य विशाल साहू आदि उपस्थित थे। हरिकिशन पावरिया महामंत्री दुर्गा संभागे ने बताया कि विभागीय मंत्री अरूण साहू से सकारात्मक चर्चा हुई है।

एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रोहित साहू ने किया पौधा रोपण

पायनियर संवाददाता < गरियाबंद
www.dailypioneer.com

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत राजिम विधायक रोहित साहू ने गरियाबंद के ग्राम पंचायत डोंगरीगाव के आश्रित ग्राम केशोडार दरपारा में पौधा रोपण किया। साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं जिला पंचायत सीईओ रीता यादव सहित स्व सहायता समूह की महिलाओं ने भी पौधे लगाए। इस अवसर पर विधायक साहू ने पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ वातावरण के लिए पौधे लगाकर उनका देखभाल अपने बच्चों की तरह करने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि प्रकृति से ही देश की प्रगति जुड़ी हुई है, ऐसे में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा यह दायित्व बनता है कि हम भी पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा में अपना योगदान दें। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक पेड़ मां के नाम



अभियान में देश का हर नागरिक अपनी महती भूमिका निभा रहा है। यह अभियान हमारी माँ और धरती माँ के प्रति हमारी श्रद्धा के भाव को प्रकट कर रहा है। आज पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी माँ और धरती माँ दोनों के नाम से पौधा लगाकर उन्हें प्रणाम कर रहा है। पर्यावरण स्वच्छ रह सके और बीमारियों से बचाव हो सके इसके लिए पर्यावरण को स्वच्छ रखना होगा। पर्यावरण को बचाने के लिए हर नागरिक को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए, ताकि पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन बना रहे। विधायक साहू ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले पीढ़ियों

को एक बेहतर एवं स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए इस मुहिम से जरूर जुड़े विधायक साहू ने कहा कि अपने घर, दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, तालाब के किनारे जहाँ भी संभव हो एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएँ दोनों के नाम से पौधा लगाकर उन्हें प्रणाम कर रहा है। पर्यावरण स्वच्छ रह सके और बीमारियों से बचाव हो सके इसके लिए पर्यावरण को स्वच्छ रखना होगा। पर्यावरण को बचाने के लिए हर नागरिक को एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए, ताकि पृथ्वी पर प्राकृतिक संतुलन बना रहे। विधायक साहू ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले पीढ़ियों

दिव्यांगजन समाज पर बोझ नहीं हैं : राज्यपाल डेका

पायनियर संवाददाता < रायपुर
www.dailypioneer.com

राज्यपाल रमन डेका के मुख्य आतिथ्य में 'दिव्य कला शक्ति' कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिसमें दिव्यांगजनों ने अपनी कला प्रविभा का दर्शन किया। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला रानी डेका काकोटी, रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि एवं पूरे देश से आये दिव्यांग उद्यमी एवं कलाकार उपस्थित थे। राज्यपाल डेका ने इस अवसर पर कहा कि दिव्यांगजन समाज पर बोझ नहीं है बल्कि राष्ट्र की प्रगति में योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को सहनशुक्ति का पत्र नहीं समझना चाहिए। उनके प्रति समाज के नजरिये में बदलाव आना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'सबका साथ-सबका विकास' के तहत समावेशी रूप से दिव्यांगजनों सहित सभी को शामिल किया गया है। दिव्यांगों



को यह ऐहसास दिलाना होगा कि वे भी समाज के लिए महत्वपूर्ण अंग हैं। उनके विकास के लिए सार्वजनिक स्थानों में सुलभ बुनियादी ढाँचा, सुगम परिवहन व्यवस्था देना होगा। बच्चों के पाठ्यक्रम में भी ऐसी कहानियां आदि शामिल करना चाहिए, जिससे उनमें दिव्यांगजनों के प्रति करुणा की भावना जगृत हो, किन्तु उनसे वे सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करें। राज्यपाल डेका ने कहा कि भारत सरकार सहित छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी

दिव्यांगजनों का जीवन-यापन सरल बनाने के लिए अनेक योजनाएँ, संचालित की जा रही हैं। दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण के साथ विभाग द्वारा कम व्यय दर पर ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजन भी शिक्षित करने के साथ ही उन्हें रोजगार के अवसर देने, व्यवसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, आवास आबंटन में प्राथमिकता देने और उनके परिवारों को विशेष सहायता देने से दिव्यांगजन भी समाज और राष्ट्र की प्रगति में बराबरी से योगदान दे सकेंगे। इस अवसर पर रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि दिव्यांगजनों में अलग तरह की विशेषताएं होती हैं और वे अनेक क्षेत्रों में बखूबी अपना दायित्व निभा रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री विरेंद्र कुमार द्वारा रायपुर में दिव्यांग पार्क बनाने की घोषणा करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

जनता की समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से करें: उद्योग मंत्री देवांगन

पायनियर संवाददाता < रायपुर
www.dailypioneer.com

उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कोण्डागांव जिले में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से सुनिश्चित किया जाए। सभी अधिकारी जिले के समग्र विकास के लिए समन्वय बनाकर कार्य करें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बैठक में जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, विद्युत व्यवस्था, कृषि, खनिज, वन और शहरी विकास सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की। वाण्यज एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते



हुए कहा कि केशकाल घाट सड़क के मरम्मत कार्य जल्द कराएँ ताकि आम लोगों को यात्रा सुविधा और सुगम हो। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत आम नागरिकों को जल प्रदाय योजना से निश्चित रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने प्रतिरत योजनाओं को शीघ्रता से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उद्योग मंत्री ने कहा कि किसानों और अन्य नागरिकों को बिना किसी बाधा के नियमित रूप से बिजली मिलती रहे। प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत आवास निर्माण कार्य की प्रगति समीक्षा में निर्माणधीन

की विस्तृत जानकारी देते बताया कि जिले के कोण्डागांव ब्लॉक के 77 गांवों में जल जीवन मिशन के तहत सफलतापूर्वक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। मिशन के तहत जिले में 1,26,713 नल कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से अब तक 98,427 कनेक्शन पूरे किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में 15,994 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 11,523 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। बैठक के दौरान खनिज प्यास निधि के कार्यों सहित एक पेड़ माँ के नाम, महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं तथा नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के परिसीमन और शहरी आवास के निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की गई।



रायपुर, लखनऊ और नई दिल्ली से प्रकाशित

हमेशा सच के साथ

RNI NO. CHHHIN/2016/70655

प्रायोजक

www.dailypioneer.com रायपुर, शुक्रवार 23 अगस्त 2024 पृष्ठ-12 वर्ष-09, अंक-03 मूल्य 3.00 ₹



विवेक न्यूज

देश के विभिन्न हिस्सों में 10 दिनों में
900 दुष्कर्म की घटनाएं : अभिषेक

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पिछले 10 दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में करीब 900 दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं। बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहा, पिछले 10 दिनों में पूरा देश आरजू कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल की घटना के खिलाफ प्रदर्शन और न्याय की मांग कर रहा है, वहीं देश के विभिन्न हिस्सों में करीब 900 दुष्कर्म की घटनाएं हुई हैं। जब लोग इस भयानक अपराध के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, तब दुख की बात है कि स्थायी समाधान पर अभी भी काफी हद तक चर्चा नहीं हुई है।

आईएचसीएल की नयी होटल जिंजर का शुभारंभ

उदयपुर। देश की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड की नगरी उदयपुर में पांच सितारा होटल जिंजर का शुभारंभ किया। कंपनी की कार्यकारी उपाध्यक्ष दीपिका राव ने शहर के शास्त्री सर्कल पर स्थित जिंजर के नये भवन का फीता काटकर इसके शुभारंभ की घोषणा की। राव ने इस अवसर पर पत्रकारों को बताया कि यह होटल ब्रांड के सिनेचर लीन लक्स फलसफ में प्रतीक है और अपने मेहमानों को आधुनिक एवं आरामदायक ठहराव प्रदान करने को समर्पित है।

अधिकारियों की लापरवाही से पैदा हुए सीवर संकट : आतिशी

नई दिल्ली। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही से शहर में पैदा हुए सीवर संकट की वजह से दिल्ली महामारी के कगार पर पहुंच गई है। आतिशी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड में जानबूझ कर वित्तीय संकट पैदा कर दिल्लीवालों का जीवन नर्क में डाला गया है। उन्होंने सीवर ओवरफ्लो की समस्या पर गंभीर चिंता जताते हुए मुख्य सचिव को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया। उन्होंने कहा है कि सीवर संबंधित संकट के समाधान की निगरानी करना मुख्य सचिव की जिम्मेदारी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताली डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की

पायनियर संवाददाता < नई दिल्ली
www.dailypioneer.com

उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज के स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ ड्यूटी के दौरान कथित दुष्कर्म और उसकी हत्या के विरोध में आंदोलनरत देशभर के डॉक्टरों को अपने काम पर तत्काल लौटने की गुरुवार को अपील की और काम पर लौटने वाले आंदोलनकारी डॉक्टरों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के साथ ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का सरकारों को निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा को पीठ ने घटना के 'स्वतः संज्ञान' मामले में सुनवाई के दौरान



जताई है कि उनमें से कुछ पर पिछले दिनों हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के कारण कार्रवाई की जा रही है। हमें आश्वासन दिया गया है कि डॉक्टर काम पर वापस लौट आएं... और (22 अगस्त 2024) के आदेश के बाद काम पर वापस आने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को राज्य के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक करके काम पर लौटने के इच्छुक डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि यह बैठक एक सप्ताह के भीतर आयोजित की जाए और राज्य सरकार दो सप्ताह के भीतर सुधारत्मक उपाय करें।

शाह ने माणिक से बात कर त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा

पायनियर संवाददाता < नई दिल्ली
www.dailypioneer.com

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा से बात की और राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। शाह ने राज्य सरकार को आवश्यकता पड़ने पर केंद्र से हस्तसंभव सहायता का आश्वासन दिया है। गृह मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि मोदी सरकार संकट की इस घड़ी में त्रिपुरा के लोगों के



साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राहत एवं बचाव कार्यों में स्थानीय प्रशासन की सहायता के लिए राज्य में नावों और हेलिकॉप्टरों के अलावा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) को भी भेज रही है। शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों एक्स पर एक पोस्ट में कहा, त्रिपुरा के सीएम डॉ. माणिक साहा से बात की और राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का राजधानी के अस्पतालों में औचक निरीक्षण



पायनियर संवाददाता < रायपुर
www.dailypioneer.com

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राजधानी रायपुर के कई अस्पतालों में औचक निरीक्षण किया। जायसवाल ने सबसे पहले मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। जायसवाल ने यहां मरीजों से बात की उन्हें मिल रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसके बाद रायपुर

गोविंदराजन पद्मनाभन प्रतिष्ठित विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित



नई दिल्ली (वार्ता)। देश में आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के अग्रदूत प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को गुरुवार को प्रतिष्ठित विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम श्रेणी में प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को 33 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुमुं ने राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार-2024 प्रदान किए। उन्होंने देश में आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के अग्रदूत प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में आजीवन योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले 13 वैज्ञानिकों को उनके संबंधित क्षेत्रों में पद-प्रदर्शन अनुसंधान के लिए विज्ञान श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

प्रदेश के किसानों को मिला 6281 करोड़ रूपए का अल्पकालीन कृषि ऋण



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर राज्य के अधिक से अधिक किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण किया जा रहा है। प्रदेश में किसानों को अब तक राज्य सहकारी बैंकों के द्वारा 2058 सहकारी समितियों के माध्यम से लगभग 6281 करोड़ रूपए का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण किया गया है। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा किसानों को 7300 करोड़ रूपए ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को उनके मांग और रकबे के अनुरूप अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जा रहा है। जबकि पिछले वर्ष आज की स्थिति में 6 हजार 193 करोड़ रूपए के अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित किए गए थे। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को खेती-किसानी की प्रारंभिक जरूरतों को पूरा करने तथा खेती-किसानी में सफलता प्रदान करने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना प्रारंभ किए गए हैं।

मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के बीच द्विपक्षीय वार्ता

वार्ता < वारसो/नई दिल्ली
www.dailypioneer.com

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने दोनों देशों के बीच संबंधों को नयी गति देने के लिए द्विपक्षीय वार्ता की। टस्क ने पोलैंड की राजधानी वारसो में संघीय चांसलरी में मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। पैतालीस वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की यह पहली यात्रा है। स्वागत के बाद मोदी ने अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिश्री भी थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा भारत-पोलैंड साझेदारी में एक नया मील का पत्थर। पोलैंड के



प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने वारसो में संघीय चांसलरी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और उनका औपचारिक स्वागत किया। पैतालीस वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की यह पहली यात्रा है। स्वागत के बाद मोदी ने अपने समकक्ष राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ बातचीत की। एक्स पर एक पोस्ट में, विदेश मंत्री ने कहा सुबह पोलैंड के विदेश मंत्री के साथ अच्छी बातचीत हुई।

जम्मू-कश्मीर के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बहाल करना कांग्रेस की प्राथमिकता : राहुल

वार्ता < श्रीनगर
www.dailypioneer.com

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस पार्टी का प्राथमिक उद्देश्य जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बहाल करना है। जम्मू-कश्मीर के दो दिवसीय दौर पर आये गांधी ने संवाददाताओं से कहा कि वह केन्द्रशासित प्रदेश और देश के बाकी हिस्सों के लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि उनका प्रतिनिधित्व सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, 'यह सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को फिर से हासिल करें। मेरा जम्मू-कश्मीर के लोगों से गहरा जुड़ाव है और मेरा उन्हें संदेश है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा उनका



समर्थन करने के लिए मौजूद है।' उन्होंने कहा कि लोग चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं और वे चाहते हैं कि हिंसा खत्म हो। अपनी भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य सम्मान और भाईचारे के जरिए 'नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलना' है। इससे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर का राज्य से केंद्र शासित प्रदेश में बदलना 'अभूतपूर्व' है। उन्होंने कहा, 'ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। केंद्र शासित प्रदेश बन गये हैं, लेकिन यह पहली बार है जब कोई राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है।

कांग्रेस ने ईडी दफ्तर का किया घेराव

विपक्ष को डराओं, धमकाओ और अपनी पार्टी में शामिल कर लो यह काम केंद्र की सरकार कर रही : बैज

पायनियर संवाददाता < रायपुर
www.dailypioneer.com



केन्द्र सरकार के द्वारा केन्द्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग तथा ईडी की कार्यप्रणाली को लेकर कांग्रेस ने देशव्यापी ईडी दफ्तर के सामने घेराव किया। छत्तीसगढ़ में भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर के सामने घेराव प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ईडी ने देश भर में 5 हजार 422 केस दर्ज किया है। जिसमें 300 केस छोड़ दे तो बाकी सभी केस विपक्ष के नेताओं का केस है। विपक्ष को डराओं, धमकाओ और अपनी पार्टी में शामिल कर लो यह काम केंद्र की भाजपा की सरकार करती है। आज तक इस तरह ईडी और आईटी का दुरुपयोग कभी नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक विचारधारा है सत्य और अहिंसा पर

चलना है। भाजपा की केन्द्र सरकार को ईडी और आईटी का दुरुपयोग को छोड़ देना चाहिये और उनके मूल काम पर लगा देना चाहिये। विपक्षी नेताओं यहां छपा मारकर परेशान किया जाता है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने झीरम में गोली खाई है कांग्रेस पार्टी हर बलिदान के लिये तैयार रहती है। ईडी, सीबीआई, आईटी से कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से सबसे बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ लड़ने

से जनता का मन उठ गया। भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था बहाल है। भाजपा सरकार मुद्दों को भटकाने के लिये कभी किसी की गिरफ्तारी और किसी के खिलाफ एफआईआर करना का काम करती है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में रहते हुये जनता के मुद्दों को उठाती है। हमारे नेताओं को जेल लड़ेंगे और जनता के हित के लिये भी लड़ेंगे। भाजपा सरकार हमारे नेताओं को जेल में बंद कर रही है और समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी डर जायेगी तो कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। भाजपा की सरकार हमारे 1 नेता को

जेल भेजती है हमारे हजारों कार्यकर्ता जेल जाने को तैयार है। जेल की दीवारें कम पड़ जायेगी और एफआईआर के पत्रे कम पड़ जायेंगे। इतिहास लिखने और इतिहास बदलने की लिये कांग्रेस पार्टी तैयार है। ये सब से हम डरने वाले नहीं है इस सबसे हम लड़ने वाले है। हमारा एक-एक कार्यकर्ता मजबूत है चाहे जो भी जांच करा लो। हमारे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। आज पूरे देश में सेन्रल एजेंसियों के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता घेराव करने को तैयार है।

खरसिया विधायक उमेश पटेल ने गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर बंधाया ढांडस

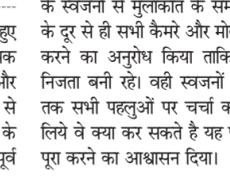


पायनियर संवाददाता < रायगढ़
www.dailypioneer.com

गैंगरेप मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए पीड़िता के परिजनों से खरसिया विधायक उमेश पटेल ने मुलाकात कर ढांडस बंधाई और दोषियों को सजा दिलाने के अलावा सरकार से पीड़िता को मदद दिलवाने में सहयोग देने के बात कही है। इस दौरान रायगढ़ के पूर्व



विधायक प्रकाश नायक भी मौजूद रहे। पीड़िता के स्वजनों से मुलाकात के समय उन्होंने पर के दूर से ही सभी कैमरे और मोबाइल को बंद करने का अनुरोध किया ताकि पीड़िता की निजता बनी रहे। वहीं स्वजनों से काफी देर तक सभी पहलुओं पर चर्चा की और उनके लिये वे क्या कर सकते है यह पूछा और उसे पूरा करने का आश्वासन दिया।



नदियों को निर्मित बनाने के लिए वाराणसी में स्थापित हुई स्मार्ट प्रयोगशाला

नई दिल्ली। गंगा और अन्य नदियों को स्वच्छ और निर्मित बनाने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों की कड़ी में भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला (एसएलसीआर) की स्थापना की गयी है, जिसका मुख्य उद्देश्य वरुणा नदी का संरक्षण करना है। यह साझेदारी भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बवारस हिंदू विश्वविद्यालय (आईआईटी-बीएचयू) और डेनमार्क सरकार के बीच एक अद्वितीय द्विपक्षीय पहल है, जिसका उद्देश्य छोटी नदियों के संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्टता लाना है।

रायपुर। राज्यपाल रमेश ठाकुर ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक वी. श्रीनिवास राव ने सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने विभागीय कार्यों की जानकारी दी।

भारत बंद का धमतरी जिले में मिला जुला रहा असर

एससी, एसटी वर्ग सुबह से शहर में घुमते रहे, जगह-जगह पुलिस बल रही तैनात

पायनियर संवाददाता धमतरी
www.dailyioneer.com

सुप्रीम कोर्ट के एससी, एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर लापू करने के सुझाव के खिलाफ दलित आदिवासी संगठनों ने भारत बंद तो बुलाया है लेकिन इस बंद को धमतरी में समर्थन नहीं मिला है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के अलावा बस एसोसिएशन ने समर्थन नहीं दिया। धमतरी में बंद मिला जुला रहा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण में क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से आदिवासी समाज सहित कुछ अन्य समाज के लोगों में भी नाराजगी देखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग को लेकर आज सर्व आदिवासी समाज, सतनामी समाज, बौद्ध समाज,वाल्मीकि



समाज द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया था व्यापारिक प्रतिष्ठानों जिसका असर धमतरी जिले में मिलाजुला देखने को मिला। बंद को चेंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन नहीं मिलने के कारण अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठानों खुली रही। वहीं पेट्रोल पंप भी खुला रहा इसके अलावा वाहनों भी नियमित रूप से चलती रही। बंद को सफल बनाने समाजजन व कार्यकर्ता सुबह से ही निकल पड़े थे वाहनों में लाऊड

रहे जिससे वाहन चालकों को परेशानी नहीं हुई। इस तरह चेंबर ऑफ कॉमर्स, बस एसोसिएशन व अन्य संगठनों का समर्थन नहीं मिलने के कारण भारत बंद के तहत धमतरी जिले में बंद का खास असर देखने को नहीं मिला। बुधवार 21 अगस्त को सुबह 8 बजे से शहर बंद कराने के लिए समाजजन सड़क पर उतर गए थे। दोपहर बाद गांधी मैदान में सभा की। बंद को सफल बनाने अजा.अजजा वर्ग ने चेंबर

ऑफ कॉमर्स से भी समर्थन मांगा था, लेकिन हमी नहीं भरी। साथ ही बस एसोसिएशन संघ ने भी समर्थन देने से मना कर दिया। धमतरी बंद कराने के लिए सर्व आदिवासी समाज, सतनामी समाज,बौद्ध समाजजन समाज पार्टी के लोग निकले थे। इसके लिए पिछले सप्ताह भर से विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ तैयारी बैठक चल रही थी। विभिन्न गाडियों में सवार होकर कार्यकर्ता अलग-अलग क्षेत्रों में बंद को सफल बनाने निकले थे। दोपहर बाद गांधी मैदान में एकत्रित होकर जनसभा की। करीब 3 घंटे तक यहां जनसभा करने के बाद दोपहर 3 बजे कलेक्टर के लिए पूरा काफिला खाना हुआ। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर कलेक्टर को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।



पायनियर संवाददाता गरियाबंद
www.dailyioneer.com

जुड़ी हुई है, ऐसे में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा यह दायित्व बनता है कि हम भी पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा में अपना योगदान दें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक पेड़ माँ के नाम अभियान में देश का हर नागरिक अपनी महती भूमिका निभा रहा है। यह अभियान हमारी माँ और धरती माँ के प्रति हमारी श्रद्धा के भाव को प्रकट कर रहा है। आज पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी माँ और धरती माँ दोनों के नाम से पौधा लगाकर उन्हें प्रणाम कर रहा है। पर्यावरण स्वच्छ रह सके और बीमारियों से बचाव बच्चों की तरह करने कि अपील भी की। उन्होंने कहा कि प्रकृति से ही देश की प्रगति

स्कूलों में नौनिहालों की सुरक्षा से भाजपा सरकार को सरोकार नहीं : विनोद चंद्राकर

बालौद जिले के कोरगुड़ा गांव की हादसे से विष्णु सरकार को सबक लेने की जरूरत

पायनियर संवाददाता महासमुंद
www.dailyioneer.com

बालौद जिले डौंडीलोहरा विखं के ग्राम कोरगुड़ा में जर्जर स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने से कक्षा 5वीं के चार बच्चों के घायल होने की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए पूर्व संसदीय सचिव व महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवन लाल चंद्राकर ने इसे बेहद शर्मनाक व सरकार की प्रशासनिक विफलता का परिणाम बताया है। चंद्राकर ने कहा कि शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पूर्व ही जर्जर स्कूलों की मरम्मत तथा अतिरिक्त भवनों का निर्माण किया जाता तो आज ये हादसे नहीं होते। चंद्राकर ने भाजपा सरकार का केवल कमीशनखोरी तथा भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि 8 माह के कार्यकाल में भाजपा सरकार



ने पूरे प्रदेश में कहीं भी नए स्कूल भवन का निर्माण नहीं कराया है। चंद्राकर ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार की लचक व्यवस्था के चलते स्कूलों की स्थिति दयनीय हो गई है। महासमुंद जिले में ही अनेक जर्जर स्कूलों में नौनिहाल अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। पिथौरा ब्लॉक के गड़बेड़ा तथा सरायपाली क्षेत्र के सिंधोड़ा संकुल के सागरपाली स्कूलों में छत से पानी टपकने तथा दीवारों पर पानी रिसने जैसी घटनाएं सामने आने के

बाद भी सरकार को बच्चों को कोई चिंता नहीं है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में ही अनेक स्कूल भवन अत्यंत जर्जर हो चुके हैं। स्थानीय गंजपारा स्कूल भवन खरपतवार तथा काई से पूरी तरह ढंक चुकी है। यहां दीवार में पानी का सिपेज आ रहा है। लेकिन, इस ओर सरकार तथा प्रशासन की नजर ही नहीं है। लगता है भाजपा सरकार को कोरगुड़ा हादसे से भी बड़े और गंभीर घटना का इंतजार है। पिछले दिनों यह बात सामने आई कि कई स्कूलों में मासूम बच्चे खतरों के बीच टपकते छत से बचने छाता लेकर कक्षा पहुंच रहे हैं। गिले फर्श पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा जिले के सैकड़ों प्राथमिक, मिडिल, हाई तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों का

अवैध गांजा बेचने वाले को न्यायालय ने 5 वर्ष की कारावास एवं 50 हजार रुपए के अर्थदंड की सुनाई सजा

गांजा बेचने वाले के विरुद्ध थाना प्रभारी अर्जुनी राजेश मरई द्वारा की गई थी वैधानिक कार्यवाही

पायनियर संवाददाता धमतरी
www.dailyioneer.com

अर्जुनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सांकारा में अवैध रूप से गांजा बेचते पाए जाने पर आरोपी ढवल राम साहू के विरुद्ध थाना अर्जुनी द्वारा चालान पेश की गई थी जिसमें 20 अगस्त को विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट ने फैसला देते हुए 5 वर्ष का कठोर कारावास और 50000 की अर्थदंड की सजा सुनाई है। 27 दिसंबर 2023 को धमतरी पुलिस थाना अर्जुनी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सांकारा के पास अवैध रूप से गांजा बेचा जा रहा है की सूचना पर थाना प्रभारी अर्जुनी ने गवाहों के साथ सांकारा निवासी ढवल राम साहू के घर छापेमारी की जहां पर 10 किलो 432 ग्राम गांजा पाया गया। जिसकी



थाना अर्जुनी में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (डू)(इड) (डू) के तहत अपराध कायम किया गया था। थाना प्रभारी निरी राजेश मरई ने विवेचना कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए सम्पूर्ण साक्ष्य संकलन,गवाहों एवं अन्य तथ्यों का समावेश कर न्यायालय में चालान पेश किया गया था। जिसको इस मामले में विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट के न्यायाधीश केएल चरयाणी ने 20 अगस्त को इस मामले में फैसला सुनाया। उन्होंने ढवल राम साहू को 5 वर्ष कठोर कारावास और 50000 रुपए अर्थदंड की सजा दी है। अर्थ दंड नहीं पटने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

एफएलएन स्टार ऑफ द वीक प्रतियोगिता आयोजित किया गया

पायनियर संवाददाता भंवरपुर
www.dailyioneer.com

शासकीय प्राथमिक शाला गौरटेक विकास खण्ड बसना में संकुल समन्वयक संतलाल मुकजी के मार्गदर्शन में एफएलएन स्टार ऑफ द वीक प्रतियोगिता आयोजित किया गया।यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एफएलएन के लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक सप्ताह में एक बार किया जाएगा। जिसमें कक्षा पहली से पांचवीं के सभी बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में एफएलएन से संबंधित गणित कौशल एवं भाषा कौशल के 10 प्रश्न लिखित और मौखिक रूप में बच्चों से पूछा गया। सबसे पहले और सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी को विजेता के रूप एफएलएन स्टार ऑफ द वीक



घोषित किया गया। इस सप्ताह के एफएलएन स्टार ऑफ द वीक के विजेता कक्षा पाँचवीं से खुशरू यादव, चौथी से टिकमलाल मांडी, तीसरी से प्रीतम यादव, दूसरी से अनुराधा धुबेल और पहली से लक्ष्मी विश्वकर्मा हैं। सभी बच्चों को गुलदस्ता से स्वागत किया गया और पुरस्कार स्वरूप एक-एक पेन दिया गया। विकासखंड शिक्षा अधिकारी जे आर डहरिया, सहायक

विकासखंड शिक्षा अधिकारी बदीविशाल जोल्हे, विनोद शुक्ला, लोकेश्वर कंवर, विकासखंड स्रोत समन्वयक पूर्णानंद मिश्रा समन्वयक डिनेन्द्र कुर्रें, रोहित पटेल अनिल साव, आरिफ बेग, तिरिथ पटेल, संतलाल मुकजी, प्रभारी प्रधान पाठक शिवकुमार साहू और टिकमचंद त्रिपाठी सहायक शिक्षक ने सभी बच्चों को बधाई एवं उनके उज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी।

संगम सेवा समिति ने किया जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ

पायनियर संवाददाता सरायपाली
www.dailyioneer.com

संगम सेवा समिति द्वारा विभिन्न क्षेत्र में सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में समिति के संस्थापक प्रखर अग्रवाल द्वारा जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम का आरंभ किया गया है जिसके तहत नगर के वार्ड क्रमांक 7 के गणमान्य नागरिकों से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा किया गया,



इसी प्रकार नगर के विभिन्न वार्डों में आम जनता से जनसंपर्क उनकी

समस्या को समझ कर समाधान का प्रयास किया जाएगा।

कलेक्टर ने दित्यांग ओमकुमारी स्मार्ट स्टिक एवं सोनमती को दिया मोटराइज्ड ट्राई सायकिल

पायनियर संवाददाता बलौदाबाजार
www.dailyioneer.com

कलेक्टर दीपक सोनी ने विकासखंड बलौदाबाजार के ग्राम लटुवा निवासी दृष्टिबाधित दित्यांग 13 वर्षीय ओमकुमारी कन्नौजे को स्मार्ट केन डिवाइस समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदान किया। उन्होंने ओमकुमारी का पृथक राशन कार्ड नहीं होने पर खाद्य अधिकारी को तलब कर तत्काल नया राशन कार्ड बनवाने के निर्देश दिए हैं। अलग



राशन कार्ड बन जाने से अब ओमकुमारी को ज्यादा खाद्यान्न मिल सकेगा। स्मार्ट केन डिवाइस सेंसरयुक्त स्टिक है जो सामने कोई बड़ी वस्तु आने पर कंपन व आवाज

देता है जिससे हाथ में लेकर चलने वाला व्यक्ति सचेत हो जाता है। इस स्टिक से दृष्टिबाधित व्यक्तियों को चलने-फिरने में काफी सहुलियत होती है। कलेक्टर ने दित्यांग

ओमकुमारी से उनके स्वास्थ्य संबंधित जायजा लेते हुए पढ़ाई के बारे में भी जानकारी हासिल की उन्होंने आगे कहा कि दृष्टिबाधितों की पढ़ाई ब्रेल लिपि के माध्यम से हो सकती है। पढ़ने के इच्छुक हो तो प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारी को ओमकुमारी की पढ़ाई के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसी तरह कलेक्टर ने बलौदाबाजार विकासखंड अंतर्गत

ग्राम खम्हारिया यदु निवासी 35 वर्षीय सोनमती धृतलहरे को मोटराइज्ड ट्राई सायकिल प्रदान किया गया। सोनमती धृतलहरे ने बताया की पढ़ाई के माध्यम से ही होगी अब मैं खुद ही अपना काम कर सकता है। उन्होंने मोटराइज्ड ट्राई सायकिल मिलने पर जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक अरविंद गेडाम उपस्थित रहे।

आंगनबाड़ी सहायिका के 59 पदों पर भर्ती हेतु 11 सितम्बर तक आवेदन आमंत्रित

पायनियर संवाददाता बलौदाबाजार
www.dailyioneer.com

महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सोनाखान एकीकृत बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी सहायिका के 59 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें आंगनबाड़ी सहायिका के 59 पदों के लिए ठाकुरदािया, पैरागुड़ा, भरका, टेमरी-2, खैरवारडीह, बफरा, पिपरछेड़ी-2, दौनाझर, डाढ़ाखार, झालपाली, कटवाझर, नवाडीह, धिरघोल, अल्दा, डिपरापारा (रिंको), पुरानीबस्ती (अ), त्रिकुटीडीपा (अ), दानीडीपा, रून्नुनुनी, नवाडीह, लुकाउपाली, तेन्दुचुवा, मेडीडीपा, तालाझर, अकलतरा, सैयभाठा, बल्दाकछर-3, दलदली, मुरुमडीह, कौहाबाहर, टेनकाडम्बरी, नदीपारा(सो), डिपरापारा(सो), बंसुलीडीह, कलमीदादर,

त्रिकुटीपारा(चां), डिपरापारा(थ), तिलसाभाठा, पकलाडीपा, सड़कपारा, बोदापाली, आम्पारा, शुक्लाभाठा, पुरानीबस्ती, मिरगिदा, बिटकुली, चन्हाट, सलिहाभाठा, जोगीडीपा, सारसडोल, देवतराई, कपपेड़ी, पोड़ी, जुनाडीह, मंगलडीपा, मुगुलभाठा, बलारनवागांव, कोरंडीह एवं अचानकपुर आंगनबाड़ी केन्द्र शामिल है। आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए आठवीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यह पद केवल महिलाओं के लिए है। आवेदन करने के अंतिम तिथि 11 सितम्बर 2024 तक कार्यालयीन समय में सायं 5.30 बजे तक कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना सोनाखान,जिला बलौदाबाजार-भाठापारा (छ.प.) के पते पर अपना आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा कर सकते है।

महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार व हत्या के विरोध में निकाला केडल मार्च, आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग महिलाओं ने अपने अधिकारों व सुरक्षा की मांगों को लेकर लगाए नारे

पायनियर संवाददाता सरायपाली
www.dailyioneer.com

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ कूर बलात्कार के बाद हत्या के खिलाफ नगर की अनेक महिलाओं ने केडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया तो वहीं इस हत्याकांड की घोर आलोचना के साथ ही भारी आक्रोश भी व्यक्त किया गया। नगर की अनेक संघ संगठन से जुड़ी महिलाओं द्वारा दुर्गा मंदिर से जयस्तंभ चौक तक एक केडल मार्च का आयोजन किया गया। यह केडल मार्च पीडित डॉक्टर के साथ हुए कूर बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के रूप में आयोजित किया गया था। इस मार्च में बड़ी संख्या में महिलाएं व युवतियां



शामिल हुए, जो न्याय की मांग के लिए सड़कों पर उतर कर आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग की गईं। जय स्तंभ चौक में आयोजित प्रार्थना सभा में एक स्वर से कहा गया कि पीडित महिला डॉक्टर के साथ हुई यह कूरता केवल एक महिला के साथ नहीं, बल्कि पूरे समाज के साथ अन्याय है। इस घटना ने शहर के लोगों को झकझोर कर रखा दिया है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस केडल मार्च का उद्देश्य न केवल पीडिता के लिए न्याय की मांग करना

था, बल्कि समाज में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाना भी था। मार्च में उपस्थित महिलाओं ने इस बात पर जोर दिया कि अब समय आ गया है कि समाज इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचे और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने और हाल ही में हुई घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाने के उद्देश्य से एक विशाल केडल मार्च का आयोजन किया गया। मार्च के दौरान महिलाओं ने अपने

अधिकारों और सुरक्षा की मांग को लेकर नारे लगाए। इस रैली में हिस्सा लेने वाले युवतियों ने भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर समाज सेविका अनिता चौधरी, अग्रवाल समाज अध्यक्ष कुसुम अग्रवाल, समाज सेविका अंजली अग्रवाल, योग शिक्षक अनू, अघरिया महिला मंडल सदस्य डॉक्टर लक्ष्मी चौधरी, फुलझर डिफेंस एकेडमी धर्मद चौधरी ने अपने अपने विचार व्यक्त किये। इस अवसर पर पतंजली योग सेवा समिति, मारवाडी समाज, अघरिया समाज, मुस्लिम समाज, सीख समाज, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल, स्काउट गार्ड से तबस्मू तथा दुष्यंत साहू ने अगुवाई की। पुलिस विभाग द्वारा केडल मार्च में पूर्ण सुरक्षा व शांति बनाये रखने उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री आवास योजना से बदल रही है कई परिवारों की जिंदगी

महतारी वंदन योजना से भी महिलाओं को मिल रहा है संबल

पायनियर संवाददाता बलौदाबाजार
www.dailyioneer.com

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार और संवेदनशील सरकार ने आवासहीन परिवारों को पक्की छत देने के लिए कृतसंकल्पित है। यह योजना न केवल लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और स्थिर आवास भी प्रदान करती है। राज्य सरकार की इसी पहल से न केवल श्रीमती भोजेश्वरी वर्मा का सपना साकार हुआ है,बल्कि यह पहल पूरे जिले में एक नई उम्मीद और



उज्वल भविष्य की किरण साबित हो रही है। आशाएं जब जीवंत रूप लेती हैं तो उसकी खुशी पूरे घर में साझा की जाती

है। ऐसा ही एक दृश्य बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम सकरी निवासी में देखने को मिला। जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों का आवास का सपना साकार हुआ है। भोजेश्वरी वर्मा ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना उनके लिए वरदान साबित हुई है। वे पुराने दिनों की कठिनाइयों को याद करते हुए बताती हैं कि कच्चे मकान में रहना काफी तकलीफदायक था। मौसम के अनुसार विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कभी छत टपकती थी तो कभी ठंड से रात भर नींद पूरी नहीं होती थी। अब पक्का मकान मिलने से उनकी ये समस्याएं दूर हो गई हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना

है,जिससे वे लोग बिना परेशानियों का अपना जीवन व्यतीत कर सकें। आज इस योजना का लाभ सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी मिल रहा है। इसके साथ ही श्रीमती भोजेश्वरी वर्मा महतारी वंदन योजना का भी लाभ ले रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा फरवरी 2024 में महतारी वंदन योजना का फॉर्म आंगनबाड़ी केंद्र में भरी थी। जिसके तहत प्रतिमाह एक-एक हजार रुपए की किस्त प्राप्त हो रही है। जिसका उपयोग उनके द्वारा अपने घर के सामान्य खर्च तथा अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कर रही है जो उन्हें सशक्त और मजबूत बनाने में सहायगी सिद्ध हो रही है उन्होंने प्रसन्नचित होकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए धन्यवाद दिया है।

है,जिससे वे लोग बिना परेशानियों का अपना जीवन व्यतीत कर सकें। आज इस योजना का लाभ सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी मिल रहा है। इसके साथ ही श्रीमती भोजेश्वरी वर्मा महतारी वंदन योजना का भी लाभ ले रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा फरवरी 2024 में महतारी वंदन योजना का फॉर्म आंगनबाड़ी केंद्र में भरी थी। जिसके तहत प्रतिमाह एक-एक हजार रुपए की किस्त प्राप्त हो रही है। जिसका उपयोग उनके द्वारा अपने घर के सामान्य खर्च तथा अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कर रही है जो उन्हें सशक्त और मजबूत बनाने में सहायगी सिद्ध हो रही है उन्होंने प्रसन्नचित होकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए धन्यवाद दिया है।

31 दिसम्बर तक किया जाएगा श्रमिक पंजीयन कार्ड नवीनीकरण

बलौदाबाजार। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सत्रिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के गठन से अब तक ऐसे पंजीकृत श्रमिक जिनके पंजीयन की वैधता समाप्त हुए 1 वर्ष या उससे अधिक समय हो चुका है, तथा जो श्रमिक पंजीयन नवीनीकरण हेतु अब तक आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे श्रमिकों से 31 दिसम्बर 2024 तक नवीनीकरण आवेदन कर सकते है। इसके पश्चात ऐसे अनवीनीकृत पंजीयन को अपंजीकृत माना जायेगा। समस्त ऐसे पंजीकृत श्रमिकों जिसका श्रमिक पंजीयन कार्ड की वैधता समाप्त हो गई हो, वह श्रमिक श्रम विभाग के (श्रमेव जयते) मोबाईल एप या श्रम विभाग के वेबसाइट या अन्य ऑनलाईन के माध्यम से नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी हेतु मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र के दूरभाष नम्बर 0771-3505050 पर संपर्क कर सकते है।

संपादकीय एमपाक्स का प्रकोप सतर्कता जरूरी

एमपाक्स का प्रकोप सारी दुनिया के लिए चिन्ता का विषय है। हालांकि, अभी परेशान होने के बजाय इसके प्रति सतर्कता जरूरी है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद अब दुनिया एक और बड़ी स्वास्थ्य चुनौती 'एमपाक्स' का सामना कर रही है जिसे पहले 'मंकोपाक्स' के नाम से जाना जाता था। यह वाइरस ओमारी परंपरागत रूप से अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती थी, पर अब यह परेशान करने वाली गति से दुनिया भर में फैल रही है। इससे दुनिया भर के स्वास्थ्य अधिकारियों में चिन्ता फैल गई है। एमपाक्स मंकोपाक्स वाइरस से फैलता है जो 'आर्थोपाक्स कुल' में शामिल है। चेचक या स्माल्पाक्स वाइरस भी इसी कुल का है। अच्छी खबर यह है कि अधिकांश मामलों में यह जानलेवा नहीं होता है और इसका इलाज किया जा सकता है। हालांकि, एमपाक्स का कोई खास इलाज नहीं है, पर अधिकांश पीड़ित कुछ सप्ताह में ठीक हो जाते हैं। अच्छे प्रतिरक्षण प्रणाली वाले लोगों में सामान्य देखभाल और दर्द निराकरण से राहत मिलती है, लेकिन कमजोर प्रतिरक्षण प्रणाली वाले लोगों को इलाज की जरूरत पड़ती है। हालांकि, यह स्माल्पाक्स की तुलना में कम घातक है, पर एमपाक्स से खासकर कमजोर प्रतिरक्षण प्रणाली वाले लोगों में गंभीर ओमारी हो सकती है। वाइरस का प्रसार मुख्यतः जवान-मनुष्य संपर्क तथा मानव-मानव संपर्क से हो सकता है। सीधे संपर्क, शरीर के द्रवों, सांस से निकलने वाली छोटो-छोटो बूंदों या बिस्तर जैसे संक्रमित स्थान से संक्रमण फैल सकता है। एमपाक्स के लक्षणों में बुखार, थिरदर, मांसपेशियों में दर्द, लसोका ग्रंथियों में सूजन, कंपकंपी तथा अक्सर चोहरे से शुरू होकर शरीर के अन्य भागों में फैलने वाले चकटे शामिल हैं।



हाल ही में कोयानावायरस वैश्विक महामारी से राहत पाने के बाद लोग एक और वैश्विक महामारी का सामना करने की स्थिति में नहीं हैं। हालांकि, अभी यह महामारी नहीं है, पर यदि रक्षात्मक कदम न उठाए जाए तो यह वैश्विक महामारी में बदल सकती है। दुनिया भर में एमपाक्स मामले बढ़ने के बाद भारतीय हवाईअड्डों पर सतर्कता बढ़ाई गई है। तथा वाइरस का प्रसार रोकने के कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक राष्ट्रव्यापी सलाह जारी कर हवाईअड्डों को जांच प्रक्रिया गहन बनाने तथा संभावित मामलों को पहचान व उनको अलग-थलग करने के प्रोटोकाल कठोरता से सुनिश्चित करने को कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन-डब्ल्यूएचओ ने अनेक क्षेत्रों में एमपाक्स मामले बढ़ने की जानकारी दी है। इससे पहले वाइरस की निर्धारित खतरे वाले क्षेत्रों में चिन्ता फैल गई है। बुखार, चकटे या लसोका ग्रंथियों में सूजन जैसे लक्षण वाले यात्रियों को और चिकित्सकीय परीक्षणों के लिए कहा जा रहा है। दिल्ली, मुंबई और बैंगलुरु जैसे शहरों में प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे महत्वपूर्ण रक्षात्मक कदम उठा रहे हैं। त्वरित अंफुलन के लिए इन स्थानों पर विशेष चिकित्सा टीमों लगाई गई हैं ताकि एमपाक्स संक्रमित किसी व्यक्ति को अलग कर उसका इलाज किया जा सके। आइए से आने वाले यात्रियों के अलावा देश से आइए वाले यात्रियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। खासकर वाइरस संक्रमित क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों को सावधानियां बरतने को कहा जा रहा है। हालांकि, भारत में अभी एमपाक्स के ज्यादा मामले सामने नहीं आए हैं, पर वाइरस को देश में जट्टे जमाने से रोकने के लिए व्यापक सुखात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जोर दिया है कि एमपाक्स का प्रसार रोकने के लिए संक्रमितों की जल्दी पहचान तथा उनको अलग-थलग करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारत जैसे धनी अर्थव्यवस्था वाले देश में एमपाक्स प्रसार के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन

आर्थिक उथलपुथल और सैनिक विद्रोह के कारण बांग्लादेश से भारत के अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध अब अनिश्चितता का शिकार हैं। वहां भारत-विरोधी भावनायें बढ़ रही हैं तथा रणनीतिक हितों पर सवाल उठ रहे हैं।

अशोक के. मंडता
(लेखक, सेनानिबृच मेजर जनरल हैं)

आर्थिक उथलपुथल और सैनिक विद्रोह के कारण बांग्लादेश से भारत के अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध अब अनिश्चितता का शिकार बन गए हैं। वर्तमान समय में वहां अनेक कारणों से भारत-विरोधी भावनायें बढ़ रही हैं तथा भारत के उस देश में रणनीतिक हितों पर सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले को प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा कि भारत बांग्लादेश को घटनाओं व खासकर वहां हिंदुओं व अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में बहुत चिन्तित है। प्रधानमंत्री के इस संबोधन के फौरन बाद 'अंतरिम सरकार' के मुखिया प्रोफेसर यूनुस ने मोदी से फोन पर बात कर उनकी सुरक्षा के बारे में आश्वासन दिया। वहां में पिछले 53 साल में हुए चौथे परोक्ष सैनिक विद्रोह का नेतृत्व पूरी तरह छत्र-संचालित आंदोलन के द्वारा हुआ। इससे प्रधानमंत्री शेख हसीना की अपनी सत्ता गंवानी पड़ी। इसका प्रमुख कारण शेख हसीना का जनता से संपर्क टूटना तथा आर्थिक परेशानियों को घटाने पर लागू लागाने में विफलता थी। छत्रों द्वारा संचालित आंदोलन में अनेक छत्रों समेत लगभग 200 लोगों और संबन्धत: इससे भी अधिक प्रदर्शनकारियों को मौत हसीना की सत्ता के लिए 'ऊंट की पीठ तोड़ने वाला आखिरी तिनका' साबित हुई। इसके बाद सेना प्रमुख-पीओएसएफ जनरल वकार-उज-जाम के सामने केवल एक ही विकल्प बचा और उन्होंने शेख हसीना को देश छोड़ कर जाने के लिए 45 मिनट का समय दिया।



'विरासत' के प्रति गुस्से की भावना भी बढ़ रही थी जिसे समय पर नहीं पहचाना गया। शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तथा मुक्ति संग्राम से जुड़े स्मारक तोड़ने की घटनाएं इसके प्रतीक के रूप में सामने आईं। बांग्लादेश में भारत-विरोधी भावनायें बढ़कने का एक कारण हसीना सरकार का भारत द्वारा आखंड बंद कर समर्थन करना था, जबकि उनकी लोकतांत्रिक पहचान लागावार गिर रही थी। इसके साथ ही बांग्लादेश में भारत-विरोधी भावनाओं के अन्य कारण भी थे जिनमें बीएसएफ द्वारा सीमा पर की गई गोलीबारी, तोखा जल का स्रावना न हो पाना तथा विलोपित कार्येडोर का प्रयोग करने को अनुमति न देना भी शामिल हैं।

भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीएफ-एनआरसी को जोरदार परोकारों ने भी भारत के प्रति बांग्लादेश में संदेह का वातावरण बना। इन परिस्थितियों में शेख हसीना को भारत में अनिश्चित काल तक शरण देने के निर्णय से भी बांग्लादेश में भारत के प्रति गुस्सा बढ़ने को आशंका है। बांग्लादेश में जुलाई और अगस्त की घटनाओं के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इनमें अनेक षडयंत्र पिट्टानों को आश्चर्यजनक रूप से बढ़वा दिया गया।

इनमें अमेरिका का नाम लेना, सोआईए द्वारा सेंट मार्टिन द्वीप पर कब्जे की इच्छा तथा पाकिस्तान, आईएसआई व चीन का नाम लेना शामिल हैं। सेंट मार्टिन द्वीप पर म्यांमार भी अपना दावा करता है। हालांकि, इनमें से कुछ पक्षों ने निश्चित रूप से परेशानियों का लाभ उठाने का प्रयास किया, पर भारत को 'इस्लामवादी' व 'जिहादी' संगठनों की खासतौर से चिन्ता करने चाहिए। हालांकि, नोबेल विजेता, उदारवादी लोकतांत्रिक व क्षेत्रीयवादी मुहम्मद यूनुस 'अंतरिम सरकार' का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि वे दरह्य है कि शेख हसीना के रिश्तेदार जनरल जमां ने इस विद्रोह में क्या भूमिका अदा की। बांग्लादेश में कोई भी सत्ता परिवर्तन बिना सेना की संलिप्तता के कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है।

शेख हसीना की सबसे बड़ी उपलब्धि एक समय अत्यन्त निर्धन बांग्लादेश को वृद्धि पश्चिम की तरफ से सबसे तेज प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था बनाना था। उसके मानव विकास सूचकांक श्रीलंका को छोड़ कर सभी क्षेत्रीय देशों से आगे थे। वेतनों पर विरोध प्रदर्शनों तथा हड़तालों व कोविड में

तबाह होने के पहले उसका गार्मेट उद्योग विश्वस्तरीय था। बांग्लादेश ने दो दशक तक 6.5 प्रतिशत की गति से प्रगति की थी और उसकी प्रति व्यक्ति आय 2600 डालर थी जो भारत से भी बहुत अधिक थी। लेकिन उसकी प्रगति को यह गाथा आईएमएफ से 4.76 बिलियन डालर कर्ज लेने और मुद्रास्फीति 10 प्रतिशत से अधिक होने के कारण नष्ट हो गई। भारत के साथ उसका व्यापार लेजी से बढ़ा और वह 18 बिलियन डालर तक पहुंच गया। यदि बांग्लादेश के साथ एकदोए हो जाते तो बांग्लादेश के निर्यात में 182 प्रतिशत वृद्धि होती। बांग्लादेश से आने वाले पर्यटकों को खंडा सबसे अधिक है और उन्होंने चिकित्सा पर्यटन को गति दी है। बांग्लादेश के साथ रक्षा संबंध बहुत अच्छे रहे और वरदान को कहा है। हालांकि, बांग्लादेश 'वार गेम्स' में भारत को शत्रु की तरह पेश करता था, पर इसके बावजूद भारत ने बांग्लादेश को रक्षा खरीद के लिए 500 बिलियन डालर की सहायता दी थी। लेकिन बांग्लादेश की सेना और एक समय जनरल जमां द्वारा निर्वात रक्षा खरीद में भारत सबसे निचले स्तर पर जबकि चीन सबसे ऊपर था। वहां विमान, पनडुब्बियां,

टैंक, तोपखाना और अन्य उपकरण मुख्यतः चीनो हैं।

वर्तमान समय में बांग्लादेश छात्र नेताओं की महात्वाकांक्षियों के कारण परेशानी में फंसा है जिनका क्रियाकलाप अंतरिम सरकार कर रही है। इस प्रकार भारत को ऐसे देश में चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जिसे जन्म देने में उसने प्रमुख भूमिका अदा की थी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों का स्वर्णिम काल वह था जब भारत के हितों को समुचित रूप से संबोधित किया जाता था। यही कारण है कि बांग्लादेश की गई सरकार शेख हसीना तथा अवामी लोग से जुड़े सभी लोगों पर निशाना लगा रही है।

वर्तमान परिस्थितियों में बांग्लादेश की सेना दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और भारत इसको उम्मीद भी कर सकता है। यदि बांग्लादेश अपने समझ आने वाली आर्थिक चुनौतियों का सामना करना चाहता है तो इसके लिए भी उसे भारत की सहायता अनिवार्य रूप से लेनी होगी। बांग्लादेश और भारत की भौगोलिक स्थिति तथा दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं की संरचना भी द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने में अपनी भूमिका अदा कर सकती है। वहां को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 2022 में भयानक आर्थिक संकट और दीवालियापन में नई दिल्ली ने कोलंबो को आइए निकालने में किस प्रकार सहायता की थी। इस सत्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि केवल छत्रों का विरोध आंदोलन ही श्रीलंका की राजनीति बदलने में सक्षम नहीं था। बांग्लादेश के एकमात्र हिंदू पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार सिन्हा को हसीना ने हटा दिया था। सुरेन्द्र कुमार सिन्हा ने कहा है कि बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है वह पूरी तरह असंबंधित है। उन्होंने 'अंतरिम सरकार' द्वारा किए अनेक परिवर्तनों को भी खेतीकित किया है। क्रॉफि या सैनिक विद्रोह में संविधान को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रशासन ने कहा है कि किसी चुनाव के पहले संविधान समीक्षा समेत संरक्षण सुधार किए जायेंगे। इस सत्र में समय लगेगा। सत्ता परिवर्तन के इस शुरुआती समय में अनिश्चितता व्याप्त है। इससे भारत को नई भू-राजनीतिक चुनौतियां सामने आ रही हैं और अब उसे प्रासांगिक पक्षों से संबंध स्थापित करने होंगे। इन चुनौतियों में शेख हसीना व अवामी लोग से व्यवहार भी शामिल है।

वर्तमान परिदृश्य में आरक्षण की आवश्यकता

सदस्यों का यह मत रहा होगा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को सर्वांगीण उथ्थान के लिए यह प्रावधान आवश्यक है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसको बढ़ाया जाना राजनैतिक मजबूरी है। सन् 1950 में जब यह प्रावधान किया गया था, तब उक्त जाति के लोगों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति क्या थी और जब-जब इस अवधि में वृद्धि की गई है, तब-तब उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में क्या अंतर आया, कितनी प्रगति हुई, कितने लोगों की आर्थिक स्थिति में वृद्धि हुई, इसका कोई अध्ययन या अनुसंधान सरकारी स्तर पर हुआ होगा ऐसा मेरा मानना है और यदि उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार हुआ है तो इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है कि आरक्षण को किस सीमा तक, कितनी अवधि तक और किस स्वरूप में जारी रखना चाहिए और यदि कोई सुधार नहीं हुआ है तब तो उसे निरंतर जारी रखने में कोई दिक्कत नहीं है। जब संविधान बना, उस समय अनुसूचित जाति एवं जनजाति में कौन-कौन सी जातियां

शामिल होंगी, उसका उल्लेख एवं जाति को उक्त सूची में शामिल करने की प्रक्रिया का उल्लेख, संविधान के अनुच्छेद 341 में कर दिया गया था। जिस प्रकार लोकसभा एवं विधानसभाओं में उक्त जाति के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुरूप अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान, संविधान में किया गया, ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 15 (4) के तहत शासकीय सेवाओं में भी उन्हें पर्याप्त अवसर मिले इसलिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति में वे जातियां शामिल की गई हैं, जो हजारों वर्षों में विभिन्न कारणों से सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से वंचित रही और इस कारण वे धीरे-धीरे विकास की ओर अग्रसर होने के बजाए पिछड़ी चली गईं। अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा, वर्ष 1979 में जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी, तब उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े की पहचान करने हेतु 'मंडल आयोग' का गठन किया और मंडल आयोग की रिपोर्ट को विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने अगस्त, 1990 में लागू कर दिया। हालांकि

संविधानिक प्रावधान न होने के कारण लोकसभा एवं विधानसभाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्थान आरक्षित नहीं है लेकिन शासकीय सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया गया जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए पूर्व में आरक्षित सीमा के अतिरिक्त थी। अब सवाल यह उठता है कि जब देश को आजाद हुए 77 वर्ष हो गये हैं तो क्या जिन जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, उनके शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है? संभवतः इसका उत्तर नहीं है क्योंकि आरक्षण का लाभ जाति को देखकर दिया जाता है न कि जिस व्यक्ति को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, उसके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर को देखकर। हो यह है कि आरक्षण के कारण जिन लोगों को उसका लाभ मिल चुका है, उन्हें ही या उनकी पीढ़ियों को ही लगातार इसका लाभ मिल रहा है और जो वास्तव में उपेक्षित या पिछड़े हैं, उनके स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ है और यही कारण है कि अभी हाल ही में दिनांक 1 अगस्त, 2024 को उच्चतम न्यायालय की 7 जजों की संविधानपीठ ने 6:1

के बहुमत से अनुसूचित जाति एवं जनजाति आरक्षण में जातियों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करने का अधिकार राज्यों को दे दिया। न्यायालय का यह भी मत था कि एक ही जाति आरक्षण का अधिक लाभ उठायेगी तो बाकी कमजोर जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा जबकि आरक्षण का मकसद वंचित वर्गों को आगे बढ़ाना है। अपने फैसले में उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति कोटे में क्रीमीलेयर लागू करने पर भी जोर दिया हालांकि उसका सभी राजनैतिक दलों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया है और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सांसदों ने इस संबंध में प्रधानमंत्री जी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और प्रधानमंत्री जी ने भी इसे लागू करने की घोषणा कर दी। क्रीमीलेयर को लागू करने के पीछे यह तर्क दिया कि संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण में क्रीमीलेयर का प्रावधान नहीं है। अब क्या केवल इस आधार पर कि संविधान में क्रीमीलेयर का प्रावधान नहीं है, आर्थिक रूप से अति वंचित दलितों के अधिकारों का हनन नहीं होगा संविधान में तो

आरक्षण का प्रावधान भी केवल 10 वर्षों के लिए था फिर जब संविधान में संशोधन कर उसकी अवधि में वृद्धि की जा सकती है तो क्रीमीलेयर का प्रावधान शामिल करने में संसद को कौन रोक रहा है। लेकिन इससे उन लोगों को अवसर नहीं मिलेगा जिन्हें आरक्षण के कारण बार बार अवसर मिलता रहता है और वे लोग पुनः वंचित रह जाते हैं जो वास्तव में आरक्षण के हकदार हैं। कुल-मिलाकर जब तक न्यायालय के क्रीमीलेयर वाले फैसले के आधार पर जातियों के वर्गीकरण के फैसले को लागू नहीं किया जाता, तब तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति में शामिल सभी जातियों का उथ्थान संभव नहीं है। इसलिए यदि हम सभी का उथ्थान चाहते हैं तो क्रीमीलेयर का प्रावधान लागू करना सामयिक एवं प्रासंगिक होगा और तभी डॉ. भीमराव अंबेडकर का वह सपना साकार हो सकेगा कि प्रत्येक वंचित व्यक्ति को बराबरी का अवसर मिले। अन्यथा जिस प्रकार उपेक्षा के कारण अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग पिछड़े रह गये उसी प्रकार इन्हीं जातियों के ऐसे लोग जिन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिला वे और भी पिछड़े जाएंगे।

वक्फ बोर्ड अधिनियम में बदलाव, कामकाज को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा

करने के लिए केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की संरचना का पुनर्गठन करना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण संशोधन में वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले भूमि का अतिवार्य सत्यापन शामिल है। इसका उद्देश्य अन्यायपूर्ण घोषणाओं को रोकना है जिससे विवाद और दुरुपयोग होता है। प्रस्तावित परिवर्तनों में यह भी शामिल है विवादायक संपत्तियों की न्यायिक जांच के लिए प्रावधान ताकि वक्फ संपत्तियों के रूप में उनकी स्थिति का पता लगाया जा सके, जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, विधेयक का उद्देश्य उन विशिष्ट खंडों को निरस्त करना है जो बोर्डों को अत्यधिक शक्तियां प्रदान करते हैं, जिससे इन शक्तियों का दुरुपयोग करने की उनकी क्षमता पर अंकुश लगता है। ये संशोधन वक्फ बोर्डों के कामकाज को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं। सरकार ने इन सुधारों के लिए सुझाव जुटाने के लिए विभिन्न मुस्लिम बुद्धिजीवियों और संगठनों से भी परामर्श किया है। जबकि सरकार के प्रस्तावित संशोधन सही दिशा में एक कदम हैं, आगे के उपाय वक्फ बोर्डों की प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं। सभी वक्फ संपत्तियों के लिए एक डिजिटलिकोर्ड-कीपिंगसिस्टम लागू करने से पारदर्शिता बढ़ सकती है। इन अभियंत्रों तक सार्वजनिक पहुंच को अतिरिक्त और जवाबदेही की अनुमति मिलेगी। काबुली विशेषज्ञों, सामुदायिक नेताओं और सरकारी प्रतिनिधियों वाली एक स्वतंत्र निगरानी समिति की स्थापना वक्फ बोर्डों की गतिविधियों की निगरानी कर सकती है और काबुली का अनुपालन सुनिश्चित कर सकती है। वक्फ बोर्ड के सदस्यों और

कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करने से काबुली, वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं की उनकी समझ में सुधार हो सकता है, जिससे वक्फसंपत्तियों का बेहतर प्रबंधन हो सकता है। निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में स्थानीय समुदाय की अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि वक्फसंपत्तियों का प्रबंधन समुदाय की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में महिलाओं को अतिवार्य रूप से शामिल करने के सरकार के प्रस्तावित प्रस्ताव के अलावा, इन भूमिकाओं में महिलाओं को सशक्त बनाने और उनका समर्थन करने के लिए विशेष कार्यक्रम और पहल बनाना महत्वपूर्ण होगा। इसमें नेतृत्व प्रशिक्षण, मेंटशिप कार्यक्रम और सुनिश्चित करना शामिल हो सकता है कि महिलाओं को वक्फ प्रबंधन के सभी पहलुओं में भाग लेने के समान अवसर मिलें। प्रस्तावित संशोधनों ने वक्फ बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करके और उनका सशक्तिकरण सुनिश्चित करके लक्ष्यों हासिल पर पड़ी मुस्लिम महिलाओं को आजाद दी है। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में महिलाओं को शामिल करना लैंगिक समानता और समावेशी निर्णय लेने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये सुधार, महिलाओं की भागीदारी और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उपायों के साथ मिलकर, वक्फ प्रणाली में विश्वास बहाल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि यह निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से संचालित हो, जिससे हमारे समुदाय के सभी सदस्यों को लाभ हो।

मालयलम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सुझावित करके शो शूटिंग को बढ़ावा देना केबनेट को रिपोर्ट अर्निश सर्वेक्षण हो गई। स्ट्रिट में रो गई बच्चों हैवन कराती हैं। पहले से वक्फ सरकार द्वारा इस रिपोर्ट को 5 वर्ष तक रखा कर रहा था और अंततः आर्योआई के जॉय भी इसे बहर लाते में लंबे जॉयगहर करने पड़े। आउटर रेश जो गंभीर रिपोर्टों को सरकारों देबाकर सचें रख लेबा हैं? केवल मलयालम वार्ड नई मुंबई व अन्य स्थानों की फिल्म इंडस्ट्री के हॉल भी इतने के लिए एक व्यापक संपर्क को हो या इसके भी बदर हैं। टैला और शोहरत की चर्चनीप में

सुविधाएं अपना सब कुछ रॉब पर लाकर फिल्म इंडस्ट्री में सुझा खाती हैं। इस उद्योग में शोषण तो सबका होता है, मगर काम केवल चिनित सुविधाओं को हो मिलाता है। इंडस्ट्री में स्थापित होने के बाद भी कई स्थानों में उनका सौका जाता रहता है। फिल्म उद्योग में महिलाओं का हर प्रकार का शोषण कोई नई बात नहीं है। इसमें अनेक अभिनेता, निर्देशक और निर्माताओं के साथ कभी-कभी तनाव भी शामिल हो रहे हैं। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए एक व्यापक संपर्क को जरूरत है।

फिल्म उद्योग में महिलायें

बिना जमीन के खसरा अभिसरण 5.17 एकड़ हो गया 6.02 जिले के राजस्व अधिकारी आंख मूंद कर दिए राजिस्ट्री, नामांतरण

पायनियर संवाददाता < जांजगीर चांपा
www.dailypioneer.com

जांजगीर चांपा जिले के हाई प्रोफाइल शासकीय जमीन घोटाला लखनपुर के शासकीय धरसे को निजी लाभ के लिए बिल्डर द्वारा सरकारी आम निस्तारी धरसे की जमीन को विलोपित करके बेजा कब्जा कर लिया गया है। राजस्व विभाग ने मामले को संज्ञान में लिया और मामले की जांच करवाकर न्यायालय तहसीलदार ने स्थगन आदेश जारी कर मौका चसा किया बिल्डर को नोटिस जारी किया गया है। संतोष जनक जवाब नहीं मिलने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। आरोप है कि बिल्डर पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण सहित शासकीय धरसा में कब्जा पाया गया है। गौर करने की बात यह है की उक्त भूमि सभी खसरो सहित 5.17 एकड़ है पर जिले के राजस्व अधिकारियों के रहमों करम से एक नया खसरा



अभिसरण किया प्रतिवेदित है जिसका नक्शा बिना स्थल निरीक्षण के आर आई के द्वारा बना दिए गया और नया नक्शा काटा गया जो जिससे अधिकारी के कृत्य पर सवाल उठने शुरू हो गया है जो घोर लापरवाही के श्रेणी में आता है और व मौके में भूमि 5.17 एकड़ है जिसे 6.02 एकड़ रजिस्ट्री कर नामांतरित कर दिया। इसके बाद राजस्व विभाग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच के लिए पटवारी को निर्देशित किया था

जांच उपरांत पटवारी ने तहसीलदार को जांच प्रतिवेदन दिया जिसमें शासकीय जमीन पर सड़क का निर्माण करना प्रतिवेदित किया गया। जिसके आधार पर जवाब पेश करने न्यायालय में तलब किया है। इसके अलावा लखनपुर के सरकारी घास (धरसा) जमीन पर कई लोगों द्वारा कब्जा किया गया है। लेकिन अधिकारियों के साथ साटु गांठ के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। कब्जाधारियों के चलते सरकारी

जमीन खत्म हो रही है। दूसरी ओर जिला प्रशासन के अधिकारी व कर्मचारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस संबंध जिला पंचायत सदस्य उमा राजेंद्र राठौर ने बताया है कड़ी कार्यवाही नहीं होने पर आगामी लोकसभा सदन में प्रश्न उठाने एवम प्रदेश के मुखिया से इस आशय की शिकायत करने की बात कही गई है वही संबंधित अधिकारी ने जानकारी में बताया की फाइल तहसील कार्यालय से मंगाया गया है।

संभागायुक्त ने ग्राम धरदेई में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का किया अवलोकन

महिलाओं से चर्चा कर आजीविकामूलक गतिविधियों की ली जानकारी



पायनियर संवाददाता < मुंगेली
www.dailypioneer.com

बिलासपुर संभाग के संभागायुक्त नीलम नामदेव एका ने पथरिया विकासखंड के ग्राम धरदेई में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क (रीपा) का अवलोकन किया और संचालन की प्रक्रिया व उससे होने वाली आमदनी की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्व सहायता

समूह की महिलाओं से चर्चा कर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में पूछा और उन्हें विभिन्न आजीविकामूलक गतिविधियों के माध्यम से आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने प्रोत्साहित किया। संभागायुक्त ने पीनट एंड मिक्सर इकाई, पीनट चिकी इकाई, आर्टिफिशियल ज्वेलरी इकाई, फर्नीचर इकाई, आरओ वाटर इकाई और मिट्टी

से निर्मित उत्पादन इकाई का अवलोकन किया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभाकर पाण्डेय, डिप्टी कमिश्नर अर्चना मिश्रा, पथरिया एसडीएम बी. आर. ठाकुर, उप संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जनपद सीईओ पथरिया सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

मानस मंच भोजली महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया

पायनियर संवाददाता < मुंगेली
www.dailypioneer.com

विकासखंड लोरमी नगर के मानस मंच भोजली महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया जिसमें मुख्य अतिथि टी आर ध्रुव रहे एवम अध्यक्षता रामजी ध्रुव ने किया एवम विशिष्ट अतिथि पूर्व जनपद सदस्य सुनीता ध्रुव रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि का स्वागत पिला चावल से तिलक लगाकर किया गया मुख्य अतिथि ने कहा छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पर्व भोजली जो मित्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाईचारे और सद्भावना का प्रतीक है। अच्छे वर्षों और फसल एवं सुख-समृद्धि की कामना के लिए रक्षाबंधन के दूसरे दिन भोजली पर्व मनाया जाता है। इसे कई स्थानों पर भुजरिया/कजलिया नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व प्रकृति प्रेम और खुशहाली से जुड़ा पर्व है। इसका प्रचलन रूप से जहां आ रहा है। इस बार यह पर्व आज यानी 20 अगस्त को मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय पर्व भोजली मनाया जाता है।



खासकर गांवों में इस पर्व को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिलता है। जहां बाजे-गाजे के साथ भोजली विसर्जित होती है। मान्यता है कि इसका प्रचलन राजा आल्हा ऊदल के समय से है। यह पर्व अच्छी बारिश, अच्छी फसल और जीवन में सुख-समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन महिलाओं द्वारा इनकी पूजा-अर्चना करके इन टोकरीयों को जल स्त्रोतों के लिए शोभा यात्रा के रूप में ले जाया जाता है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के सांस्कृतिक करमा सुआ डंड नृत्य प्रस्तुति दी गई एवम अतिथियों द्वारा भोजली रानी की पूजा पाठ कर देवी गंगा देवी गंगा, लहर तुंगा गंगे गीत

से पूजा अर्चना कर भोजली रानी को गंगा स्नान के कर के साथ मानस मंच से पैदल रेली निकालकर मनियारी नदी शिवघाट में गंगा स्नान किया गया जिसमें मुख्य रूप से दयाराम ध्रुव, राम नेताम मूरज कोल, देवा मार्को, रूपराम ध्रुव राजेश ध्रुव, राजू ध्रुव, अरविंद ध्रुव, चंद्रू ध्रुव, कृष्णा ध्रुव, रामवतार ध्रुव, महेंद्र ध्रुव, बृषभूषण ध्रुव, जागसिंह नेटी, दूजे ध्रुव, इतवारी ध्रुव, प्रेमसिंह ध्रुव, उपेन्द्र जगत धनीराम ध्रुव, रानू मरावी, सुनंदा ध्रुव, पुष्पा, ऊषा ध्रुव, दुर्गेश्वरी ध्रुव, राजेश्वरी ध्रुव, राजीम ध्रुव, प्रमिला ध्रुव, शिवकुमारी ध्रुव, सोनिया ध्रुव, बड़ी की संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित रहे।

जिले में 21 अगस्त को भारत बंद का रहा मिला-जुला असर

पायनियर संवाददाता < सक्ती
www.dailypioneer.com

अनुसूचित जाति जनजाति समाज द्वारा 21 अगस्त को बुलाए गए भारत बंद का शक्ति जिले में मिला-जुला असर देखा गया, शक्ति शहर में जहां व्यापारियों ने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 12 से 3:00 तक दुकान बंद रखी, तो वहीं निजी स्कूलों में स्कूल संचालकों ने भारत बंद को देखते हुए पूर्व में ही छुट्टियां घोषित कर दी थी, तथा बारादार शहर में भी देखा जाए तो भारत बंद का मिला-जुला असर रहा एवं कुछ दुकानें खुली रही तो कुछ बंद रही जब बारादार शहर में आयोजकों की रैली ने प्रवेश किया, तो उस समय लोगों ने अपनी दुकान बंद कर दी थी, बारादार शहर में भारत बंद को लेकर नगर पंचायत बारादार के अध्यक्ष विजय सूर्यवंशी, भाजपा नेता ओमप्रकाश कुरें, भाजपा जिला चिकित्सा प्रकाश के संयोजक डॉक्टर धिरेन्द्र कुमार खूटे, विजय लहरे, प्रदीप बंजारे, देव कुमार भारद्वाज,



पूर्व जनपद पंचायत सदस्य बंशीधर खानडे सहित अनेकों सामाजिक कार्यकर्ता शहर में बंद करवाने निकले तो वहीं भारत बंद को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति समाज ने रैली का भी आयोजन किया, जो कि शक्ति जिले के विभिन्न प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए शक्ति, बारादार शहर में प्रवेश की, तथा शक्ति शहर के अग्रसेन चौक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शक्ति को जापन सौपा गया तथा शक्ति शहर में भी व्यापारियों ने 20 अगस्त को हुई बैठक में ही दोपहर 12:00 से 3:00 बजे तक बंद करने पर अपनी सहमति प्रदान की थी तथा व्यापारियों ने यह बात भी कह दी थी कि प्रदेश स्तर पर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इस बंद में सहयोग करने के लिए अपनी असमर्थता जता दी है।

विकलांग शल्य शिविर में 21 अगस्त को 17 दिव्यांग जनों का खोला गया टांका



पायनियर संवाददाता < सक्ती
www.dailypioneer.com

रोटरी क्लब आफ बिलासपुर एवं अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद के संयुक्त तत्वाधान में बिलासपुर के जिला चिकित्सालय में 13 अगस्त 2024 को आयोजित विकलांग शल्य शिविर में 17 दिव्यांग जनों की शल्य क्रिया की गई थी, तथा इन दिव्यांग जनों का 21 अगस्त को विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपस्थिति में टांका खोला गया एवं सभी दिव्यांग जनों का कैलीपर्स का भी नाप लिया गया एवं टांका खोलने के बाद पुनः प्लास्टर लगाकर उन्हें आवश्यक दवाइयां देकर उन्हें घर की ओर रवाना किया गया, साथ

ही 13 अक्टूबर 2024 को उपरोक्त सभी दिव्यांग जनों को फिर से बुलाया गया है ताकि इनका संपूर्ण प्लास्टर हटाया जा सके एवं सभी दिव्यांग जनों को आगामी एक माह के लिए आवश्यक दवाइयां भी दी गईं। इस दौरान प्रमुख रूप से जहां डॉक्टर अजय पंथ्या सहित पैरामेडिकल स्टाफ में दुर्गा यादव, बगू टंडन, महेश पटेल, भोला पाल, प्रसन्ना डोंगरे सहित जिला अस्पताल बिलासपुर के पैरामेडिकल स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा, तो वहीं अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद की ओर से राष्ट्रीय महामंत्री मदन मोहन अग्रवाल, राष्ट्रीय संगठन मंत्री डीपी गुना, मुरारी लाल परमार, आर गेंदले सहित अन्य

सदस्य मौजूद रहे एवं परिषद के सभी सदस्यों ने दिव्यांग जनों को कहा कि आप सभी चिकित्सकों द्वारा बलाए गए एवं उनके द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार सावधानियां रखें एवं दवाइयों को समय पर लें तथा अगली तारीख में आप सभी जरूर पहुंचें, ताकि शल्य क्रिया से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त की जा सके वहीं दिव्यांग जनों में भी इस शल्य क्रिया के बाद काफी प्रसन्नता देखी गई तथा उनके चेहरे पर मुस्कान थी एवं उन्होंने कहा कि अब वे ऑपरेशन के बाद स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर चल सकेंगे इसके लिए भी पूरी आयोजन समिति का साधुवाद ज़ापित करते हैं।

महिला जागृति शाखा शक्ति के पदाधिकारी पहुंचे चंद्रपुर की प्रांतीय बैठक में

पायनियर संवाददाता < सक्ती
www.dailypioneer.com

आदिशक्ति मां चंद्रहासिनी देवी की पावन नगरी चंद्रपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रांतीय मारवाड़ी युवा मंच की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में महिला जागृति शाखा शक्ति के पदाधिकारी-सदस्यों ने भी सहभागिता की है, तथा शक्ति शाखा की पूर्व अध्यक्ष नीरा नरेश गेवाड़ी, शक्ति शाखा अध्यक्ष उषा आनंद अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष गुड्डी देवी अग्रवाल एवं पूर्व सचिव रितु पवन अग्रवाल इस जरीकरिणी की बैठक में शामिल हुए हैं, तथा चंद्रपुर में आयोजित इस बैठक में जहां महिला जागृति शाखा शक्ति के पदाधिकारियों का अतिथ्य शाखा द्वारा आत्मीय स्वागत भी किया गया, तो वहीं महिला जागृति शक्ति शाखा के पदाधिकारियों ने बताया कि चंद्रपुर में आयोजित जागृति शाखा विगत प्रदेश से मंच के सभी सदस्य पहुंचे हुए हैं, तथा सदस्यों में उत्साह देखा जा रहा है, एवं महिला जागृति शाखा शक्ति के सदस्यों ने मां चंद्रहासिनी देवी के मंदिर



में जाकर मत्था भी टेका, तथा क्षेत्र की सुख, शांति, खुशहाली की कामना भी की, ज्ञात हो की शक्ति की मारवाड़ी युवा मंच महिला जागृति शाखा विगत लगभग 25 वर्षों से एक सक्रिय शाखा के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए हुए हैं तथा 22 अगस्त को प्रदेश कार्यकारिणी के बैठक में भी महिला

जागृति शाखा शक्ति को विशेष रूप से बैठक में आमंत्रित किया गया है, एवं इस बैठक में शामिल होने के बाद पदाधिकारी- सदस्यों ने मंच के वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी मुलाकात की, तथा बैठक के सुंदर आयोजन के लिए चंद्रपुर के सदस्यों का भी धन्यवाद व्यक्त किया।

साइबर ठगी मामले में रायगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता 75 लाख की ठगी करने वाले 14 आरोपी पकड़े, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की डीलरशिप के नाम पर की थी ठगी

पायनियर संवाददाता < रायगढ़
www.dailypioneer.com

साइबर ठगी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए रायगढ़ पुलिस ने 75 लाख की साइबर ठगी के मामले में 14 आरोपियों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में मोबाइल फोन, एटीएम, बैंक पासबुक के अलावा नदरी रकम बरामद किया है। आरोपियों के द्वारा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की डीलरशिप के नाम हुई थी ठगी की घटना को अंजाम दिया था। मिली जानकारी के मुताबिक खरसिया थाना क्षेत्र में एक बड़े साइबर ठगी मामले का पर्दाफाश करते हुए रायगढ़ पुलिस ने 75 लाख रुपये की मोबाइल फोन में संलिप्त एक अंतरराज्यीय साइबर ठग गिरोह के



14 सदस्यों को बिहार की राजधानी पटना के अलावा अलग-अलग जिलों से गिरफ्तार किया है। रायगढ़ पुलिस ने आरोपियों के पास से ठगी के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले 40 मोबाइल, 49 एटीएम, बैंक पासबुक और नकदी रूपये बरामद किया है।

पुलिस ने बताया कि आरोपियों में एक पोस्टमैन सहित एक युवती भी शामिल थी। आरोपियों के द्वारा इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की डीलरशिप के नाम खरसिया के एक व्यवसायी से ठगी की घटना को अंजाम दिया गया था।



फेसबुक में विज्ञापन देखा था पीडिअर-रायगढ़ एसपी दिव्यांग पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संपूर्ण घटना का खुलासा करते हुए बताया कि पीडिअर व्यवसायी ने करीब डेढ़ से दो माह पहले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की डीलरशिप के लिए फेसबुक पर एक

विज्ञापन देखा और दिए गए नंबर पर संपर्क किया। खरसिया थाने में दर्ज हुआ था अपराध-कॉलर ने खुद को कंपनी का प्राधिकृत कर्मचारी बताया और धीरे-धीरे पीडिअर से विभिन्न शुल्कों के नाम पर 75 लाख रुपये ठग लिए। जब

डीलरशिप नहीं मिली और आरोपियों ने और पैसे की मांग की, तब व्यवसायी को ठगी का अहसास हुआ और उन्होंने खरसिया थाना में शिकायत दर्ज कराई। थाना खरसिया में अज्ञात मोबाइल धारकों के विरुद्ध धारा 318, 61(2)(ए) पंजीबद्ध किया गया। सामाह भर तक चला आपरेेशन-पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल ने डीएसपी साइबर सेल अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। घटना के 24 घंटे के अंदर इस 9 सदस्यीय टीम ने बिहार में कई स्थानों पर छापेमारी की और एक हफ्ते चले इस लंबे आपरेेशन में बैंक खातों की जांच, मोबाइल नंबरों के विश्लेषण और बैंक सीसीटीवी फुटेज खंगाले।

सुप्रीम कोर्ट के दिये गये फैसले के विरोध में भारत बंद का असर नगर में भी देखने को मिला

मुंगेली। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये फैसले के विरोध में भारत बंद का असर नगर में भी देखने को मिला। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठाने दोपहर दो बजे तक बंद रही, और बंद को समर्थन दिया। सतनाम भवन से रेली निकाल कर मुंगेली भ्रमण करते हुए सीटीकोतवाली थाना के पास पहुंच कर तहसीलदार को जापन सौपा गया। गौरतलब हो कि छत्तीसगढ़ सतनाम महासंघ, भीम रजिमेंट मुंगेली एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं सामाजिक कार्यकर्ता तथा समस्त एस सी, एटी संगठन के संयुक्त तत्वाधान में 21 अगस्त को भारत बंद के आवहन किया था। जिसका असर नगर में भी देखने को मिला, चेंबर आफ कॉमर्स मुंगेली ने भी इस बंद को समर्थन प्रदान किया था। जिसके चलते नगर सहित आस पास के सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखीं, वहीं सुरक्षा के लिहाज से कई स्कूलों में भी बच्चों को छुट्टी दे दी गई, इस पुरे मामले पर छत्तीसगढ़ सतनाम महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास खण्डेकर ने बताया कि हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये फैसले में क्रीमीलेयर का विरोध करते हैं, इस बंद मे आवश्यक सेवाओं को छुट्ट दे गई है, जिसके चलते पेट्रोल पम्प, मेडिकल स्टोर, अस्पताल खुले रहे। वहीं बसया नेता समारू भास्कर ने कहा कि फैसले में क्रीमीलेयर का विरोध करते हैं।



विवादों में धिरी पीओ नमिता ठाकुर को मनोरा से भी हटाने की मांग को लेकर सरपंचों ने विधायक रायमुनी भगत को सौंपा ज्ञापन

समय पर भुगतान नहीं करने और कई विभागीय अनियमितताओं को लेकर हुई है



पायनियर संवाददाता < जशपुरनगर
www.dailypioneer.com

जनपद जशपुर में पदस्थ प्रोग्राम ऑफिसर नमिता ठाकुर को स्थानांतरण मनोरा जनपद के लिए हाल में किया गया है। मनोरा उनके पहुंचने से पहले ही मनोरा जनपद पंचायत के दर्जनों ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि सरपंच उन्हें अपने विकासखंड में नहीं आने देने की मांग को लेकर विधायक रायमुनी भगत के पास 21 अगस्त को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल समय पर भुगतान नहीं करने से लेकर कई विभागीय

अनियमितताओं की शिकायत से पीओ ठाकुर धिरी हुई है।

यह थी शिकायत -लेखापाल और बड़ी मैडम के द्वारा योजनातर्गत कोई भी कार्य समय पर नहीं किया जाता है और ना ही

कार्य होने की जानकारी दी जाती है। कार्य पूर्ण करने के बाद बिल एम आई एस के लिए देने पर बिल राशि का जब तक 3 नही दिया जाता है तब तक बड़ी मैडम फाइल को देखती भी नहीं है। अगर पैसा

नहीं दे तो महीनों तक फाइल पड़ा रहता है। महोदय मनरेगा में भुगतान वर्ष में 02 या 03 बार ही होता है उस पर मैडम के द्वारा महीनों तक टाला जाता है और भुगतान से पहले पैसा लिया जाता है।

लंबी पदस्थापना पर थे सवाल

मैडम कई वर्षों से जनपद जशपुर में पदस्थ हैं और वो यहाँ की लोकल रहने वाली हैं जिसके कारण नेतागिरी करती हैं। लेखापाल के द्वारा ग्राम रोजगार सहायकों का वेतन बनाने के लिए भी पैसा मांगती हैं। अगर पैसा जा दे तो वेतन भी नहीं बनाती जिसके कारण रोजगार सहायकों को 03-04 माह तक पैसा नहीं मिलता।

जिला कार्यालय संलग्न की मांग

करडीह, सुरजुला, हरी और करदना ग्राम पंचायत के सरपंचों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन में यह कहा है कि जशपुर जनपद में पदस्थ पीओ ठाकुर के खिलाफ दर्जनों शिकायत हैं जिसपर जांच चल रही है। ऐसे में मनोरा में पदस्थ करने से यहां की छवि भी धूमिल होगी जोकि आपके प्रमुख कार्य क्षेत्र में आता है। इसलिए उन्हें जिला कार्यालय में संलग्न किए जाने की मांग की गई है।

जशपुर एसपी शशि मोहन सिंह की पशु तस्करी मामले में सलिप्त वाहनों को राजसात कार्रवाई पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने दी बधाई

कलेक्टर डॉ. मित्तल और एसपी सिंह ने लोदाम थाने में ली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस

पायनियर संवाददाता < जशपुरनगर
www.dailypioneer.com

छत्तीसगढ़ से झारखण्ड की ओर बूचड़खाना के लिए अवैध रूप से परिवहित किये जा रहे 10 प्रकरणों में 13 मवेशी वाहन को जिला प्रशासन ने राजसात की कार्यवाही की है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को त्वरित गति से राजसात करने के लिए पुलिस अधीक्षक जशपुर को टेलिफोनिक बधाई दी जिन्होंने त्वरित गति से राजसात की कार्रवाई किया है एवं इस वास्तु अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट भी किया।



किया गया एवं राजसात के लिएप्रतिवेदन कलेक्टर जिला-जशपुर को भेजा गया।

इन्हें किया गया राजसात

- पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर 10 प्रकरण में 13 वाहनों पर राजसात की कार्यवाही कलेक्टर एवं जिला ब्युजिफिकरी जिला-जशपुर द्वारा आदेश पारित किया गया।
- (1) टुक क्रमांक जेएच01एपी/9416
- (2) पिकअप वाहन क्रमांक जेएच01ईवी/4710
- (3) टाटा सूटो क्रमांक जेएच08ए/7899
- (4) पिकअप वाहन क्रमांक जेएच01ईवी/14710
- (5) पिकअप वाहन क्रमांक जेएच01एफएर/2481
- (6) पिकअप वाहन क्रमांक जेएच01ईटी/1547
- (7) पिकअप वाहन क्रमांक जेएच01एफएफ/4925
- (8) पिकअप वाहन क्रमांक जेएच09ई/7804

- (9). पिकअप वाहन क्रमांक जेएच03/एल9806
- (10). पिकअप वाहन क्रमांक जेएच01एफई/9799
- (11). पिकअप वाहन क्रमांक जेएच01एफएर/2481
- (12). पिकअप वाहन क्रमांक जेएच01एफजे/2568
- (13). पिकअप वाहन क्रमांक जेएच19ई/7954

36 प्रकरणों में 43 आरोपी 431 गौवंश मुक्त-जनवरी से अब तक गौ-

तस्करी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कुल 36 प्रकरणों में 43 आरोपियों को गिरफ्तार कर 431 गौवंशों को तस्करी होने से बचाया गया। गौ तस्करी द्वारा तस्करी करने में पीकअप वाहन एवं ट्रक का प्रयोग करते हैं। इस दौरान लगातार पुलिस कार्यवाही में तस्करी से कुल 26 वाहन को जात किया गया है जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 02 से 2.5 करोड़ लगाया गया है। अधिकतर वाहन झारखण्ड रजिस्ट्रेशन का होना पाया गया है।

पशु तस्करी से जब्त किए गए वाहनों को राजसात की कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से की गई है। पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर गृह मंत्री ने टेलीफोन के माध्यम से बधाई दी है। पुलिस का यह अभियान निरंतर जारी रहेगा।

शशि मोहन सिंह, एसपी जशपुर
पशु तस्करी रोकथाम मामले में पुलिस प्रशासन ने सराहनीय कार्य किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों में पशु संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 13 वाहनों को राजसात किया गया है। इसकी लीलाजी की प्रक्रिया भी जल्द पूरी कर ली जाएगी।

डॉ. रवि मित्तल, कलेक्टर जशपुर

कमिश्नर कावरे की पहल: रायपुर संभाग में 42 पदों पर जल्द होगी अनुकंपा नियुक्ति



संभागायुक्त ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की संभागास्तरीय कलेक्टरस कॉन्फ्रेंस

रायपुर संभाग में शामिल सभी पांच जिलों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए मिले 42 आवेदनों पर जल्द ही कार्रवाई पूरी होकर प्रभावितों को सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता खुल गया है। संभागायुक्त महादेव कावरे ने संभाग के पांचों कलेक्टरों को इन प्रकरणों पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। कावरे ने यह निर्देश वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग स्तरीय कलेक्टरस कॉन्फ्रेंस में दिए। उन्होंने धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद जिले के कलेक्टरों को उनके जिलों में लंबित 18 अनुकंपा

नियुक्ति आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा। रायपुर जिले में लंबित 24 आवेदनों के निराकरण के लिए संभागायुक्त ने सक्षम अधिकारी की अध्यक्षता में तत्काल समिति गठित कर कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में कावरे ने सरकारी दफ्तरों में समय पर अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश भी कलेक्टरों को दिए। कावरे ने कहा कि निर्धारित समय पर कर्मचारी शासकीय कार्यालय में पहुंचें। साथ ही कार्यालय भी निर्धारित समय में खुलें। उन्होंने सभी कार्यालय में अधिकारी व कर्मचारियों के नाम की पड्डिकाएं लगाने को भी कहा। कलेक्टर कांफ्रेंस में संभाग के पांचों जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत के सीईओ और अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टरस कॉन्फ्रेंस में कावरे ने ग्रामीण क्षेत्रों में सॉलिट और लिक्विड कचरे के निष्पादन के बारे में विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कचरे को अलग-अलग करने के लिए ग्राम पंचायतों में बने मंगीकंचन केंद्र या शोड निर्माण की समीक्षा की तथा शेष ग्राम पंचायतों में भी जल्द से जल्द ऐसी व्यवस्था करने के निर्देश दिए।

प्रदेश के विकास पुरुष, कुशल जननायक
छत्तीसगढ़ के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री
आदरणीय
श्री भूपेश बघेल जी
को जन्मदिन की
हार्दिक शुभकामनाएं

23 अगस्त

सुशील आनंद शुक्ला
(अध्यक्ष-प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग)

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने किया जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर का औचक निरीक्षण

अव्यवस्थाओं को तत्काल निराकृत करने के लिए सख्त निर्देश
पायनियर संवाददाता < रायपुर
www.dailypioneer.com



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने अपने न्यायालय में सभी सूचीबद्ध प्रकरणों की सुनवाई उपरांत जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर का औचक निरीक्षण किया। सर्वप्रथम सिन्हा ने जिला न्यायालय बिलासपुर के पुराने भवन के समस्त कक्षा का निरीक्षण

किया। न्यायालय भवन में जगह-जगह सीपेज देखकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। भवन की कई दीवारों में दरारें और कोर्ट रूम की दीवारों में भी सीपेज-जगह सीपेज की समस्या दिखी। कॉरीडोर में छत से पानी टपकने के कारण कॉरीडोर में पानी जमा हो रहा था और इसी तरह गार्डन

में गमले व पौधे अस्त-व्यस्त पाये गये साथ ही न्यायालय की वाहन पार्किंग व्यवस्था भी अस्त-व्यस्त थी। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने इसके उपरांत जिला न्यायालय, बिलासपुर के नवीन भवन में स्थित कोर्ट रूमों का भी निरीक्षण किया गया। नवीन भवन की स्थिति भी संतोषजनक नहीं पायी। कॉरीडोर में पानी देखकर प्रधान जिला न्यायाधीश से उसका कारण पूछा गया जिसके संबंध में जानकारी दी गयी कि ए.सी.

के पानी के कारण कॉरीडोर गीला हो रहा है। इसके तत्काल निराकरण हेतु निर्देशित किया गया। निर्माणाधीन नवीन वाहन पार्किंग का भी निरीक्षण किया और उपस्थित इंजीनियरों को कार्य नियत समयावधि में पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया। मुख्य न्यायाधीश सिन्हा के निरीक्षण की सूचना पर कलेक्टर, बिलासपुर अनीश कुमार शरण व अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण जिला न्यायालय, बिलासपुर में उपस्थित हुये।

23 Aug. 2024 Pride Of Raipur

"एत पुर त्कृत नौ लो अद्भुत, अतीविक, त्कृत, अतिविकृत, अतिविकृत, 5000 फीट का विशाल संज्ञ, जो बत विश्व दिखें। इतने सौ फीट अलग-अलग व अतिविकृत। इस दुर्लभ संज्ञ का हिस्सा बनें।"

इस दुर्लभ संज्ञ (पुस्तक) अपने घर लायें
संपर्क - 98271-22886

M A K AZAD COLLEGE OF PHARMACY, RAIPUR (C.G.)
Since - 2004
Approved by PCI New Delhi
Affiliated with CSVTU Bhalai
ADMISSION / REGISTRATION OPEN - 2024-25
B Pharmacy - D Pharmacy
XII Science - PCB / PCM
B Pharmacy lateral entry
CHOURASIYA COLONY NAV DURGA NAGAR RAIPUR
9329621221, 9425214413, 9981224037, 7714913335
email: 10 - maheshbhatnagar@rediffmail.com
For online registration Visit: www.makazadpharmacy.com

TENSILE SHADE
WE PERSENT ONLY THE BEST
CAR PARK SHADE
WEATHER PROTECTION
tensile + membrane + structure
R. B. Plus 81091 11313
RAIPUR 86028 11220

Magnetic Mosquito Net Curtain
Keeps Mosquitoes Out
Lets Fres Air and Cool Breeze In
LAXMI TRADING COMPANY
Millennium Plaza, Banstali, G.E. Road, Raipur (C.G.)
Contact : +91 93031 47175

होमलोन व माईगेज लोन
10 लाख से 10 करोड़ तक
राष्ट्रीयकृत एवं प्रतिष्ठित बैंक द्वारा
होम लोन ब्याज दर मात्र 8.70%*
माईगेज लोन ब्याज दर मात्र 9.50%*
सर्वोत्तम होमलोन को इंतजार करने के बजाय अभी अप्लाइ कर लें।
ब्याज दर पर 8.70%*
होम लोन दर पर 9.50%*
SHRI SIDDHI VINAYAK FINACE
Near Samudayik Bhawan, Jorapara, Raipur
Mob.: 9329002356

Shree Vijay Sales
Near Ganesh Vinayak Eye Hospital Opp Colors Mall, Dhamtari Road, Pachpedi Naka Raipur, Mob. 9993376888

Home Construction
HOUSE Planning | Construction Work (with or without Materials)
SOQ for bank Loans | Building Materials Supplying | Landscaping
All Electrical and Plumbing Services | Consultancy Services
Under Supervision of a well experienced Civil Engineer
@ Raipur
M : 82239-70000
86029-59274
M/s. SHEKHAR SAHAY
Shop# 139, 1st Floor, Progressive Point, Lalpur, Raipur

Cartridge Refilling
Refilling @ Your Door Step
JB Mall, Lower Ground Floor, M.G. Road, Raipur (C.G.)
Callaway Print Your Demographic with Us.
9302787900, 9425211789

विज्ञापन हेतु जगह उपलब्ध है।
9329846567
9827146567

विज्ञापन के लिये संपर्क करें : 9827146567, 9329846567



छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री

मान. श्री **भूपेश बघेल**



श्रीमती रिमता बघेल



चैतन्य बघेल
(बिदू भैया)



प्रमोद सिंह राजपूत
अध्यक्ष
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुम्हारी

जी को **23** अगस्त



जन्मदिन



के. रवि कुमार श्री मनहरण यादव श्री धनेश पटेल

की

हार्दिक बधाई शुभकामनाएँ..



राजेश्वर सोनकर
अध्यक्ष - न.पा.प. कुम्हारी



श्रीमती जानकी धुव श्रीमती नैतू रावते श्री युजेंद्र साहू श्री राकेश कुरी श्रीमती शारिता टंडन श्री महेश सोनकर श्रीमती लता खेचर श्रीमती शक्ति यादव श्रीमती ललिता किशोर सोनकर श्री जोमनरायण वर्मा श्री प्रमोद चदाकर श्रीमती कुमारी बाई निवार

विनीत :- ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुम्हारी

मान. श्री भूपेश बघेल जी
पूर्व मुख्यमंत्री छ.ग.

छत्तीसगढ़ के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री

श्री भूपेश बघेल जी

को जन्मदिन की

हार्दिक शुभकामनाएँ

23
अगस्त

श्री कृष्णा चव्वाकः
सभापति, नगर निगम भिलाई चरोदा

श्रीमती संतोषी निवाड
एम.आई.सी सदस्य

श्रीमती दीपिका वर्मा
एम.आई.सी सदस्य

श्रीमती देवकुमारी भलावो
एम.आई.सी सदस्य

श्री एस. वेंकट रमना
एम.आई.सी सदस्य

श्री मोहन साहू
एम.आई.सी सदस्य

श्री एम. ज्योती
एम.आई.सी सदस्य

श्री ईश्वर साहू
एम.आई.सी सदस्य

श्री मनोज डहरिया
एम.आई.सी सदस्य

श्रीमती उमेश्वरी चौधरी

श्री प्रदीप चन्द्रा

श्री संतोष चन्द्रा

श्री हेमन्त चन्द्रा

श्रीमती शारदा पदमकर

श्री एस. साहू

श्री अनिमेष चन्द्रा

श्री मनोज चन्द्रा

श्री तेजेंद्र ठाकुर

श्रीमती भारती राम सूर्यवंशी

श्री रवीन्द्र हरपाल

श्री ललित दुर्गा

श्रीमती सुमना चन्द्रा

श्री कामता साहू